



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 524]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1979/अग्रहायण 21, 1901

No. 524] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 1979/AGRAHAYANA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय  
(सिंचाई विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1979

का.आ. 792(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रियक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ. 4055, तारीख 6 अक्टूबर, 1969 द्वारा, अन्तर्राष्ट्रियक नदी नर्मदा और उसकी नदी घाटी की दाबत जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन किया था ;

और उक्त अधिकरण ने उसे निर्दिष्ट विषयों के संबंध में अन्वेषण किया तथा अपनी एक रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार की अग्रणीत की थी जिसमें, वे तथ्य दर्शाते हैं जो उसके समक्ष आए थे और उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका विनिश्चय भी दिया गया है ;

और उक्त विनिश्चय पर विचार करके, केन्द्रीय सरकार तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, की सरकारों ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, उक्त अधिकरण को कतिपय विषय निर्दिष्ट किए थे और इस प्रकार निर्दिष्ट विषयों पर अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा के अधीन एक और रिपोर्ट अग्रणीत की है जिसमें ऐसे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन दिए गए हैं जो उसने ठीक समझे हैं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण द्वारा उसकी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शनों के संदर्भ में यथा उपान्तरित उक्त अधिकरण के विनिश्चय को प्रकाशित करती है।

अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शनों द्वारा उपान्तरित रूप में नर्मदा जल विवाद अधिकरण का विनिश्चय

'अधिकरण का अन्तिम आदेश और विनिश्चय

खण्ड 1: आदेशों की प्रवर्तन की तारीख

यह आदेश उक्त तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसका इस अधिकरण के विनिश्चय अन्तर्राष्ट्रियक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन, राजपत्र में प्रकाशित होते हैं।

खण्ड 2: सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा जल की उपयोग्य मात्रा का आदधारण

अधिकरण यह अवधारित करता है कि 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा के जल की उपयोग्य मात्रा 28 मिलियन एकड़ फुट (34,537.44 एम०क्यू०एम०) पर निर्धारित की जानी चाहिए।

खण्ड 3: नर्मदा जल की उपयोग्य मात्रा का प्रतापन

(1) अधिकरण यह आदेश करता है कि नर्मदा जल की उपयोग्य मात्रा में से, (क) मध्य प्रदेश 18.25 मि०ए०फु० (22,511.01 मि०क्यू०मी०) अंश का हकदार है, (ख) गुजरात 9 मि०ए०फु० (11,101.32

मि०क्यू०मी०) घंश का हकदार है, (ग) राजस्थान 0.5 मि०ए०फु० (816.74 मि०क्यू०मी०) घंश का हकदार है और (घ) महाराष्ट्र 0.25 मि०ए०फु० (308.37 मि०क्यू०मी०) के घंश का हकदार है।

(2) यह और स्पष्ट किया जाता है कि प्रभाजन का सम्बन्ध वास्तविक विकासियों से है, न कि उपयोग किए गए उपयोग से;

(3) प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने जल घंश के जल उपयोग के स्वरूप में और अपने राज्य क्षेत्र में नर्मदा तल के भीतर या बाहर फायदा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में, ऐसे परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, जैसे वह आवश्यक समझे।

#### खण्ड 4: प्रतिरिक्त जल और करस्थान के संबंध में आदेश

(1) किसी जल वर्ष में, अर्थात् 1 जुलाई से अगले कलेंडर वर्ष की 30 जून तक, उपयोग्य प्रवाह के 28 मि०ए०फु० (34,537.44 मि०क्यू०मी०) के प्राधिक्य में नर्मदा का उपयोग्य प्रवाह, आर्बंटन के निम्नलिखित अनुपात में प्रभाजित किया गया है, अर्थात् :—

मध्य प्रदेश के लिए 73, गुजरात के लिए 36, महाराष्ट्र के लिए 1 और राजस्थान के लिए 2;

(2) यदि 1 जुलाई से अगले कलेंडर वर्ष की 30 जून तक के किसी जल वर्ष में आर्बंटन के लिए उपयोग्य जल की उपलब्धता 28 मि०ए०फु० (34,537.44 मि०क्यू०मी०), से भी कम हो जाती है तो सभी विभिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश के लिए 73, गुजरात के लिए 36, महाराष्ट्र के लिए 1 और राजस्थान के लिए 2 के अनुपात में बांटी जानी चाहिए;

(3) किसी जल वर्ष में उपलब्ध उपयोग्य जल में, 1 जुलाई को उपलब्ध भण्डारित जल के आधार पर उस तारीख को यथा निर्धारित पूर्वतन जल वर्ष से अग्रणीत जल सम्मिलित होगा;

(4) किसी तारीख को उपलब्ध उपयोग्य जल में सौदाय प्रवाह सम्मिलित होगा किन्तु विभिन्न जलाशयों में से वाष्पीकरण के कारण हुई कमी उसमें से निकाल दी जाएगी।

(5) यह उल्लेखनीय है कि कई वर्षों में भरण अवधि में, उस अवधि के दौरान भण्डारण अपेक्षाओं को पूरा करने और निकासी के पश्चात् कुछ अधिशेष जल होगा। यह समुद्र में बह जाएगा। उसका केवल कुछ भाग सरदार सरोवर नदी तल बिजलीघर में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग्य होगा, और शेष बेकार जाएगा। यह वांछनीय है कि वह जल जो अन्तिम नदी तक बिजलीघर में शक्ति का उत्पादन किए बिना बेकार जाएगा, पक्षकार राज्यों को, जिस विस्तार तक वे चाहें, उपयोग करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

इसलिए गुजरात को, यह निर्देश दिया जाता है कि जब कभी जल शक्ति उत्पादन किए बिना समुद्र में बेकार जाना आरम्भ हो, या वह ऊपरी नेजिंग स्टेशनों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह प्रत्याशा करता है कि जल इस प्रकार बेकार जाएगा, तो वह नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) और सभी सम्बद्ध राज्यों के अभिहित प्रतिनिधियों को सूचित करेगा और वह उन्हें तब भी सूचित करेगा, जब ऐसा प्रवाह रुक जाता है। ऐसे प्रवाह की अवधि के दौरान ऐसे पक्षकार राज्य, जिनके अलाशय छलक रहे हैं और छलकला जल अन्यतः भण्डारित नहीं किया जा सकता, उक्त जलाशयों से बहाव का ऐसा उपयोग कर सकेंगे, जैसा वे चाहें, और पक्षकार राज्यों द्वारा ऐसे उपयोग की गणना उन्हें आर्बंटन प्रवाह में नहीं की जाएगी, किन्तु ऐसे जल का उपयोग किसी उपघारित अधिकार की स्थापना नहीं करेगा।

#### खण्ड 5: प्रभाजन आदेश के प्रवर्तन की अवधि

खण्ड 3 और 4 में साम्यापूर्ण आर्बंटन के संबंध में हमारे आदेश, राजपत्र में अधिकरण के विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से 45 वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी भी समय पुनर्विलोकन के अधीन रहने हुए, किए गए हैं;

#### खण्ड 6: नवगांव नहर का पूर्ण प्रवाह स्तर

अधिकरण यह अवधारित करता है कि सरदार सरोवर से जल प्राप्त करने वाली नवगांव नहर का पूर्ण प्रवाह स्तर, उसके शीर्ष रेगुलेटर पर 91.44 मी० ( + 300') नियत किया जाना चाहिए और उसकी तल ढलान शीर्ष से 290 कि०मी० (180 मील) तक, अर्थात् जहाँ से सौराष्ट्र शाखा जल प्राप्त करती है, 12,000 में 1 के हिमाब से होता चाहिए। उस बिन्दु से राजस्थान सीमा तक तल ढलान 10,000 में 1 के हिमाब से होता चाहिए। ये तल ढलान पारस्परिक करार से गुजरात और राजस्थान द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी। गुजरात और राजस्थान, उस जल के कारण जिसकी उपलब्धता उनके घंश के भीतर संभावित होगी, प्रत्येक द्वारा अपेक्षित नहर धारिता का विनिश्चय करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

#### खण्ड 7: सरदार सरोवर बांध का पूर्ण जलाशय स्तर और अधिकतम जल स्तर

अधिकरण यह अवधारित करता है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई पूर्ण जलाशय स्तर पर +138.68 मी० (+455') और अधिकतम जल स्तर पर +140.21 मी० (+460') नियत की जानी चाहिए। गुजरात तबनुसार बांध का मन्तिमण हाथ में लेगा और उसे पूरा करेगा।

#### खण्ड 8: लागत और फायदे में हिस्सा बाँट :

(1) (1) अधिकरण यह अवधारित करता है कि किसी भी दिन नहर के शीर्ष और नदी तल बिजलीघरों के नवगांव पर उत्पादित शुद्ध शक्ति में से मध्य प्रदेश का घंश 57 प्रतिशत होगा; महाराष्ट्र का घंश 27 प्रतिशत होगा और गुजरात का घंश 16 प्रतिशत होगा।

(2) पक्षकार राज्य, अनुसूचित सन्निर्माण कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित निधियों में अपने घंश वार्षिक किस्तों में उपलब्ध करेंगे और राजपत्र में अधिकरण के अन्तिम आदेश और विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष के भीतर सरदार सरोवर बांध को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

(2) अधिकरण निम्नलिखित और आदेश करता है :—

(1) नवगांव पर नदी तल और नहर बिजलीघरों में उत्पादित शक्ति सामान्य स्वचयाई में जमा की जाएगी।

(2) स्टेशन सहायकों के लिए अनुज्ञात करने के पश्चात् स्वचयाई में दस बार पर उपलब्ध शक्ति में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(3) उपयुक्त हकदारी शिखर भार के लिए मशीन धारिता की उपलब्धता और किसी एक दिन में उत्पादित कृप ऊर्जा, दोनों को, लागू होती है।

(4) किसी भी दिन के लिए विद्युत और ऊर्जा की हकदारी, सम्बद्ध राज्यों द्वारा पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त को या पारस्परिक करार के अधीन किसी अन्य भागीदार राज्य को बेची जा सकती है। किन्तु इसे प्रभावित पक्षकारों में किए गए पृथक करार या कार्यकारी, प्रबन्ध के अधीन के मिश्रण, अग्रदान नहीं किया जा सकता है।

(5) गुजरात, पक्षकारों के बीच यथा तय का गई संरेखा के साथ-साथ और यदि कोई करार नहीं किया गया है तब, ऐसी संरेखा के साथ-साथ, जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारी विनिश्चित करे, गुजरात राज्य सीमा तक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को विद्युत की आर्बंटन मात्रा प्रवाह करने के लिए आवश्यक पारेषण लाइनों का सन्निर्माण और उनका अनुरक्षण करेगा। गुजरात राज्य सीमा के परे पारेषण लाइनों का सन्निर्माण और अनुरक्षण, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपने अपने राज्यों में करेंगे।

(७) गुजरात राज्य में बिजलीघरों और अनुलग्न संक्रमों, जिनके अन्तर्गत सभी बिजली प्रसिद्धि और प्रसिद्धि प्रणाली का संशोधन, अनुसंधान और प्रचालन गुजरात राज्य या इस राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी करेगा।

(7) बिजली घरों का नियंत्रण प्राधिकारी, जहाँ तक जल के उपयोग का संबंध है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के निर्देशों का अनुसरण करेगा।

(8) बिजलीघरों के प्रचालन की स्कीम, जिसके अन्तर्गत दिन के विभिन्न भागों के दौरान, विभिन्न पक्षकार राज्यों के लिए उपलब्ध शक्ति और जुटा या जाने वाला भार भी है, प्रत्येक मास के प्रारम्भ से कम से कम एक सप्ताह पूर्व राज्यों के बीच तय की जाएगी और राज्यों के बीच करार के अधीन या आपातकालीन स्थितियों में के सिवाए, मास के दौरान परिवर्तित नहीं की जाएगी। जब कभी सरदार सरोवर शक्ति प्रक्षेत्र, प्रादेशिक या राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड के साथ संयोजित हो जाता है, तो सरदार सरोवर शक्ति प्रक्षेत्र का प्रचालन ऐसी परिवर्तित प्रणाली की शर्तों से शासित होगा। किन्तु उस स्थिति में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को, इन प्रादेशों के अनुसार सरदार सरोवर शक्ति प्रक्षेत्र से शक्ति और ऊर्जा का अपना हक प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।

(9) नवगांव प्रक्षेत्र के शक्ति भाग की पूंजी लागत में निम्नलिखित होंगे :—

(क) यूनिट-III विद्युत संक्रमों और स्विचयार्ड तक, जिसके अन्तर्गत वह भी है, उससे संबंधित नियंत्रण संक्रमों को पूर्ण लागत।

(ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को शक्ति प्रदाय के लिए सन्निहित गुजरात राज्य में पारेषण लाइनों की पूर्ण लागत।

(ग) सामान्य सुविधाओं, जैसे बांध और अनुलग्न संक्रम, अर्थात् सरदार सरोवर परियोजना की यूनिट 1 की शुद्ध लागत का, जिसमें से जमा रकमों की, यदि कोई हो, घटा दिया जायेगा, में 56.1 प्रतिशत।

(घ) नर्मदा सागर बांध से व्युत्पन्न अनुप्रवाह फायदों के लिये मध्य प्रदेश को दिए गए अमावस्य का 56.1 प्रतिशत।

(10) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऊपर (9) के अनुसार निकाली गई सरदार सरोवर शीर्ष संक्रम के शक्ति धारा की पूंजी लागत का क्रमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत गुजरात को संभाल करेगा यह राशि, जब तक पूंजी संक्रम पूरे नहीं हो जाते, वार्षिक किस्तों में संवत् की जायेगी। प्रत्येक किस्त प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में संक्रम के बजट-ग्रंथों के आधार पर निकाली जायेगी और वित्त वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक ग्रंथों के अनुसार गुजरात और समायोजित की जायेगी।

(11) ऊपर (10) के अनुसार मंदायी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक वर्ष सरदार सरोवर प्रक्षेत्र के प्रचालन और अनुसंधान लागत का क्रमशः 57 प्रतिशत और 27 प्रतिशत भी गुजरात को देंगे। ये संदाय भी प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में बजट ग्रंथों पर आधारित होंगे और वर्ष के अंत में वास्तविक लागत के अनुसार समायोजित किए जायेंगे।

(12) इसमें ऊपर अन्तर्निहित विदेशों के होते हुए भी पक्षकार राज्य पारस्परिक करार द्वारा, शक्ति के विभाजन और उसके

लिये संदाय की बाबत किसी भी विदेश को परिचालित, संशोधित या उपांतरित कर सकेंगे।

खण्ड 9: सरदार सरोवर परियोजना की प्रवेसा के लिए मध्य प्रदेश द्वारा नियमित रूप में छोड़ा जाने वाला जल

अधिकरण, नियमित रूप में छोड़े जाने वाले जल की मात्रा और रीति के संबंध में निम्नलिखित आवेश करता है :—

पक्षकार राज्यों ने यह तय कर लिया है और अधिकरण ने सारीख 8 अक्टूबर, 1974 के अपने आवेश में यह विनिर्णय कर दिया है कि सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा में 75 प्रतिशत निर्भर योग्य जल की उपयोग्य मात्रा, 28 एम ए एफ (34,537.44 मि० क्यू० मी०) पर निर्धारित की जानी चाहिये। किन्तु 75 प्रतिशत निर्भर योग्यता का वास्तविक अन्तःप्रवाह केवल 33,316.29 मि० क्यू० मी० (27.01 एम ए एफ) है और इसे, वाष्पीकरण से होने वाली कमियों और पुनः उत्पादन की बाबत छूट को छोड़कर, विभिन्न जलाशयों में भिन्न बढ़ाने द्वारा 28 एम ए एफ (34,537.44 मि० क्यू० मी०) की उपयोग्य मात्रा तक लाया जाता है। सरदार सरोवर पर 28 एम ए एफ (34,537.44 मि० क्यू० मी०) में से 11,101.32 मि० क्यू० मी० (9 एम ए एफ) की व्यावस्था गुजरात के लिये और 0.5 एम ए एफ (616.74 मि० क्यू० मी०) की व्यवस्था राजस्थान के लिये की जाती है। सरदार सरोवर पर अवेशों को मध्य प्रदेश प्रदायों से और नर्मदा सागर के नीचे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अवेशों की अधिशेष तथा मध्यवर्ती जलाशयों के अन्तःप्रवाह से पूरा किया जाना है; महेश्वर से छोड़ा गया जल 10,015.86 मि० क्यू० मी० (8.12 एम ए एफ) भाती है मासिक रूप में छोड़े गए जल को एकत्रित करने के लिये मध्य प्रदेश द्वारा छोड़े जाने वाले जल की मात्रा, प्रति मास 834.65 मि० क्यू० मी० (0.677 एम ए एफ) होगी। किन्तु नदी प्रणाली में वास्तविक अन्तःप्रवाह वर्ष प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होगा, अतः मध्य प्रदेश द्वारा छोड़े जाने वाले जल की मात्रा भी भिन्न भिन्न होगी।

जुलाई से अक्टूबर तक की धरण अवधि के दौरान अन्तःप्रवाह की अविव्यवधानी मौसम के प्रारम्भ में नहीं की जा सकती। केवल अक्टूबर में ही यह पूर्णतः ज्ञात होगा कि विशिष्ट वर्ष सामान्य वर्ष है या किस सीमा तक अधिशेष या कमी वाला वर्ष है। अतः सामान्यतः धरण अवधि के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा छोड़ा जाने वाला जल लगभग 28 एम ए एफ (34,537.44 मि० क्यू० मी०) उपयोग्य मात्रा देने वाले वर्ष के आधार पर होगा। जुलाई मास और अगस्त का आरम्भिक भाग खरीफ बुवाई के लिये महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि इस अवधि के दौरान विनियामक प्रबंध द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी पक्षकारों को जल का सम्यक ढंग उपलब्ध हो जाये।

पूर्ववर्ती दो पैरों में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम आवेश करते हैं कि विनियमन और जल गणना के लिए विस्तृत नियम, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण होने लिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार बनायेगा। किन्तु ये मार्गनिर्देश संबंध राज्यों के बीच करार द्वारा परिवर्तित, संशोधित या उपांतरित किये जा सकेंगे।

(1) किसी जल वर्ष (1 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक) में 75 प्रतिशत निर्भर योग्य 28 एम ए एफ (34,537.44 मि० क्यू० मी०) उपयोग्य प्रदाय का विभाजन पक्षकार निम्नलिखित रूप में करेंगे।

मध्य प्रदेश — 18.25 एम ए एफ (22,511.01 मि० क्यू० मी०)  
गुजरात — 9.00 एम ए एफ (11,101.32 मि० क्यू० मी०)  
राजस्थान — 0.50 एम ए एफ (616.74 मि० क्यू० मी०)  
महाराष्ट्र — 0.25 एम ए एफ (308.37 मि० क्यू० मी०)

28.00 एम ए एफ

(2) किसी जलवर्ष में उपयोग्य प्रदायों का अधिशेष या कमी पक्षकार राज्य उसी अनुपात में साध्य सीमा तक बाँटेगा, जिसमें उपर (1) में उनके प्राबलित्व अंश है अधिशेष जल का उपयोग प्रथमतः धारिता तक जलाशयों को भरने के लिये किया जाएगा और तत्पश्चात् उसका उपयोग सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिये केवल तभी किया जाएगा, जब ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया हो।

(3) 30 जून को विभिन्न जलाशयों के चालू भण्डारों में उपलब्ध जल की गणना अगले जल वर्ष में बाँटे जाने वाले अन्तःप्रवाह के रूप में की जाएगी।

(4) किसी जल वर्ष में राजस्थान और गुजरात का जल अंश सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक जल ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो अधिकारी विनिष्ट या अनुमोदित करे और नियमित रूप में छोड़े जाने वाले जल के निदेशों को दृष्टि में रखते हुए, युक्तियुक्त सामान्य दर पर मध्य प्रदेश उत्तारेगा।

(5) प्राधिकरण, मध्य प्रदेश द्वारा छोड़े जाने वाले जल का ऐसा निवेशन करके यह सुनिश्चित करेगा कि अगले दस दिन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये सरदार सरोवर में पर्याप्त उपयोग्य जल हर समय बना रहे किन्तु शर्त यह होगी कि मध्य प्रदेश की अनुपातिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद मध्य प्रदेश में भण्डारों में जल उपलब्ध बना रहे। इस प्रयोजनार्थ गुजरात और राजस्थान 10 दिन का अवधि की अपनी अपनी अपेक्षाएं पर्याप्त समय पूर्व सूचित करेंगे।

(6) प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा जल वर्ष में उपयोजन, प्रत्येक मुख्य और मध्यम परियोजना के नगर मुख्य पर वास्तविक दैनिक निस्सारण के आधार पर अंकित किया जायगा। गौण संकमों के लिए यह, विभिन्न फसलों के लिये सिंचित क्षेत्र के, प्रत्येक फसल के लिये नदी मुख भूमि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर, आधार पर अंकित किया जायगा। पम्पन स्कीमों के लिये नदी, उसकी उपनदियों या जलाशयों से सिंचाई चरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिये, लिए गए जल की गणना, पम्पों की निम्न धारिता और उनके चलने के बंटों की संख्या के आधार पर की जायेगी। प्रति पड़ताल के लिये प्रत्येक पम्पन स्कीम द्वारा मौसम क्रम और फसल—क्रम से सिंचित क्षेत्र की अभिलिखित किंदा जायगा और यदि उपयुक्त दो पद्धतियों द्वारा प्राप्त जल की मात्रा में अन्तर आता है, तो, प्राप्त जल के संबंध में प्राधिकरण का विनिश्चित अंतिम होगा।

(7) गुजरात और राजस्थान के लिये नवगांव नहर के लिये सरदार सरोवर से निकाले गये जल की मात्रा नवगांव नहर शीर्ष पर की जायेगी। राजस्थान के लिये छोड़े गये जबकि माप गुजरात राजस्थान सीमा पर की जायेगी। राजस्थान को प्रदाय करने में नहर में हुई जल हानि का अवधारण नहर का सन्निर्माण किए जाने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा किया जायगा और राजस्थान के अंश में उसकी संगणना की जायेगी।

सरदार सरोवर के बिजली घर टर्बाइनों की मार्फत नदी में छोड़े गये जल का माप उसके द्वारा उत्पादित शक्ति के आधार पर और जो जल अधिप्लव मार्ग द्वारा रिस गया है उसकी माप अधिप्लव मार्ग पर की जायेगी।

गुजरात अपने अधोनाद उपयोग के लिये विनिश्चित मांग करके सरदार सरोवर से जल छोड़ सकेगा और ऐसे छोड़े गये जल की गणना उसके अंश के रूप में की जायेगी। अधोनाद उपयोग के लिये ऐसा जल टर्बाइनों की मार्फत छोड़ा जायेगा और इस प्रकार उत्पादित शक्ति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच विहित अनुपात में बाँटी जायेगी। गुजरात की विशेष मांग को छोड़कर सरदार सरोवर से नदियों को छोड़ा गया जल, गुजरात के अंश रूप में नहीं गिना जायेगा।

मध्य प्रदेश और यथास्थिति, महाराष्ट्र में प्रयोग के लिये सरदार सरोवर से लिया गया जल, उस राज्य के जल के हिस्से में गिना जायेगा।

(3) बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिये जल लेखा 10 दैनिक अवधि के रूप में रखा जायेगा। किसी मास की अन्तिम 10 दैनिक अवधि

उस मास के दिनों की संख्या के अनुसार 11 दिन, 10 दिन या उससे कम की हो सकेगी। छोटी स्कीमों के लिये जल लेखा फसली मौसमों के अनुसार अर्थात् खरीफ (जुलाई से अक्टूबर तक) रबी (नवम्बर से मार्च तक) तथा ग्रीष्म (अप्रैल से जून तक) रखा जायेगा। पम्पन स्कीमों और चरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिये यह लेखा मासिक रूप में रखा जायेगा।

(9) छोटी और पम्पन स्कीमों द्वारा किसी वस दैनिक अवधि में जल के उपयोग को अन्तिम रूप से उसी रूप में गिना जायेगा जैसा कि जल वर्ष में फसल अवधि के दौरान औसत उपयोग के आधार पर तत्समान अवधि के लिए था। किन्तु अन्तिम जल लेखा उपर (6) के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(10) प्रत्येक राज्य ऐसे आंकड़े और जानकारी जिसकी प्राधिकरण अपेक्षा करे और मांगें, प्राधिकरण को देगा और उसकी इच्छा रखने वाले किसी पक्षकार राज्य को उपलब्ध करायेगा।

(11) प्राधिकरण मास में कम से कम एक बार, या यदि जल के छोड़े जाने में किसी परिवर्तन का निदेश देना आवश्यक समझा जाता है तो कितनी ही बार मध्य प्रदेश द्वारा दस दिन में छोड़े गये जल के पुनर्विलोकन की व्यवस्था करेगा वह ऐसा करने के लिये किसी व्यक्ति को अभिहित कर सकेगा।

(12) प्राधिकरण किसी राज्य या राज्यों द्वारा पूर्ववर्ती जल वर्ष के दौरान उपयोग किए गए उस जल का यदि कोई है, जो प्राधिकृत उपयोग से अधिक है, पश्चात्पूर्व जल वर्ष में उन संबंधित राज्य या उन संबंधित राज्यों के अंश या अंशों में से जिन्होंने अधिक उपयोग किया है, कटौती करके अन्तिम समायोजन करने के लिये निदेश देगा और उस राज्य या उन राज्यों की पूर्ति करेगा जिन्हें कम प्रदाय प्राप्त हुआ है। राजस्थान को किसी भी वित्त उसकी मांग से 10 प्रतिशत के उपर प्रदाय किए गए जल को गुजरात द्वारा उपयोग में लाए गए जल के रूप में गिना जायेगा।

(14) प्राधिकरण अगले जल वर्ष के अंत तक पक्षकार राज्यों की सरकारों को जल वर्ष के लिये वार्षिक जल लेखा ठीक अगले जल वर्ष के अगस्त मास के अंत तक भेज देगा। प्रत्येक राज्य लेखा पर धनता अभिमत व्यक्त कर सकता है और या उसमें उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर, प्रशुद्धि यदि कोई है, बता सकता है। आवश्यक उपान्तरण करने के पश्चात् प्राधिकरण 21 अक्टूबर तक जल वर्ष का वार्षिक जल लेखा प्रत्येक पक्षकार राज्य को भेजेगा। प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष वार्षिक जल लेखा प्रकाशित कराएगा।

खण्ड 10—जल के ऐसे नियमित छोड़े जाने के लिये गुजरात मध्य प्रदेश को भुतान करेगा।

(1) मध्य प्रदेश, नर्मदा सागर बांध एक बार एल 282.13 मी०एम (860 फीट) के सन्निर्माण का कार्य आरम्भ करेगा और सरदार सरोवर बांध के सन्निर्माण के साथ साथ या उससे पूर्व पूरा कर देगा।

(2) अधिकरण यह भी आदेश देता है कि गुजरात प्रति वर्ष नर्मदा सागर बांध का निर्माण कार्य आरम्भ होने के वर्ष से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में नर्मदा सागर बांध मध्ये प्रतिवर्ष खर्च का 17.63 प्रतिशत मध्य प्रदेश खाते में जमा करेगा। इसे आरम्भ में बजट मार्बटन के आधार पर जमा खाते किया जायेगा जिसका समायोजन वास्तविक वर्ष के अनुसार वर्ष के अंत में किया जायेगा सन्निर्माण के पश्चात् अनुकरण पर होने वाले खर्च को सन्निर्माण खर्च के रूप में नहीं माना जायेगा।

खण्ड 11: जलमालावस्था, भूमि अर्जन और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी निदेश

उपखण्ड 1: रिसालाएं:—

1(1) भूमि 'भूमि' शब्द का अर्थ, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में (जिसे इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) यथापरिभाषित होगा अर्थात् भूमि शब्द के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फांदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई कोई चीजें हैं।



1(2) निर्वासित व्यक्ति:—निर्वासित व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व से उस क्षेत्र में, जिसे स्थायी या अस्थायी रूप से जलमग्न किया जाना है, साधारण रूप से निवास कर रहा है, या खेती कर रहा है या कोई व्यापार, उपजीविका या आजीविका कर रहा है या लाभ के लिये कार्य कर रहा है।

1(3) "कुटुम्ब" (1) कुटुम्ब के अन्तर्गत पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे और ऐसे अन्य व्यक्ति हैं जो कुटुम्ब के मुखिया पर आश्रित हैं उदाहरणार्थ, विधवा माता।

(2) प्रत्येक अवयव पुत्र को एक पृथक् कुटुम्ब के रूप में माना जायेगा उप खण्ड II—अनिवार्य रूप से अजित की जाने वाली भूमि।

II(1) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार सरोवर परियोजना के लिये सरदार सरोवर के एक और एल+138.38 मीटर (455 फुट) नीचे स्थित प्रार्वेट स्वामित्व की सभी भूमि का और उसमें के ऐसे सभी हिस्सों का जो संबंधित राज्यों के नहीं हैं, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन अर्जन करेंगे। यदि उपर्युक्त के आधार पर किसी व्यक्ति की संलग्न धृति की 75 प्रतिशत या अधिक भूमि को अनिवार्य रूप से अजित किया जाना है तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण संलग्नक धृति के अनिवार्य अर्जन के लिये विवश कर सकेगा।

II(2) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अंतर्गत उन सभी भूतों सहित उनका असुलमन भूमि का जो जो एक और एल+138.68 मी० (455 फु०) और एल डब्ल्यू० एल+ 141.21 मीटर (460 मी०) के बीच स्थित है और जो एम० डब्ल्यू एल+ 141.21 मी० (460 फु०) के परिणाम स्वरूप पश्चजल से प्रभावित है, अजित करेंगे।

II(3) सरदार सरोवर में उच्चतम स्तर पर पश्चजल स्तर, केन्द्रीय जल आयोग, मध्य प्रदेश और गुजरात से परामर्श करके निर्धारित करेगा।

उपखण्ड III—भूमि अर्जन और पुनर्वास आदि के लिए प्रतिकर देने की भावना गुजरात का दायित्व।

III(1) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पूर्वोक्त रूप में अजित किए जाने के लिए अपेक्षित भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए या उसको बाधित उनके द्वारा किए गए सभी खर्चों या उनके अन्तर्गत प्रतिकर, प्रभार और व्यय भी हैं, भुगतान करेगा।

III(2) गुजरात, मध्य प्रदेश सरकारी भूमि और संरचनाओं के लिए उन सिद्धांतों पर, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संघोद्धिखित सिद्धांतों के अनुरूप हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत संघ को प्रतिकर देगा। यदि यथा पूर्वोक्त संवेद्य प्रतिकर के संबंध में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भारत संघ के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में से कोई राज्य या भारत संघ विवादग्रस्त मामले को माध्यस्थता के लिए निर्देशित कर सकेगा। एक पक्षकार के रूप में गुजरात और दूसरे पक्षकार के रूप में यथास्थिति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य या भारत संघ, अपना एक एक मध्यस्थ नाम-निर्दिष्ट करेगा। मध्यस्थों के बीच मतभेद होने की दशा में, ऐसा विवाद या मतभेद किसी ऐसे निर्णायक को निवेष्ट किया जाएगा जिसकी नियुक्ति इस निमित्त भारत के मुख्य न्यायाधिश उन व्यक्तियों में से करेंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं। यथास्थिति, मध्यस्थों या निर्णायक का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकार होगा और उनके द्वारा प्रभावित किया जाएगा।

III(3) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उनके संबंधित राज्यक्षेत्रों में गुजरात के लिए अजित या उनका हस्तान्तरित सभी भूमि की

भावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भूराजस्व संहिताओं के अनुसार भू-राजस्व देगा।

III(4) गुजरात, ऐसे कितना प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारकों, पुरा-शालाओं अथवाओं, पूजा के धार्मिक स्थान या मूर्तियों को, जिनके सरोवर सरोवर के अंतर्गत जलप्लावन के कारण प्रभावित होने का संभावना है, हटाने या पुनर्स्थापित के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा किए गए सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का करेगा और ऐसा भुगतान कर दिए जाने की दशा में, जल-प्लावन द्वारा प्रभावित होने पर उनका बाधित होने किंसा पूर्वा प्रतिकर का, जिनका उचित हानि इसके पूर्व किया गया है, भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

III(5) गुजरात निर्वासित व्यक्तियों और निर्वासित कुटुम्बों के उनके अपने अपने क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए इनमें इनके प्रागे अन्तर्निष्ठ निदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनके द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान करेगा।

III(6) गुजरात, भूमि अर्जन और पुनर्वास और अन्य ऐसे विभागों के कमेन्सिजन्ट के लिए जिनके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे अर्जन और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए आवश्यक मामलों, स्थापन प्रभार मध्ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्थ का उनका भुगतान करेगा।

उपखण्ड IV : पुनर्वास के लिए उपबंध

IV(1) वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार निर्वासित कुटुम्बों की संख्या मध्य प्रदेश के 158 ग्रामों में 6147 और महाराष्ट्र के 27 ग्रामों में 456 होगी। गुजरात उन कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए जो गुजरात में प्रवास करना चाहते हैं, इनमें प्रागे वर्णित प्राधारों पर सरदार परियोजना के विशाल क्षेत्र में, गुजरात में पुनर्वास ग्रामों की स्थापना करेगा। उन निर्वासित कुटुम्बों के लिए जो गुजरात में प्रवास नहीं करना चाहते हैं, गुजरात इनमें प्रागे वर्णित प्राधारों पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उनके अपने अपने राज्य क्षेत्रों में ऐसे ग्रामों की स्थापना के लिए खर्च, प्रभार और व्यय देगा।

IV(2)(i) वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार आर एल 106.68 मीटर (आर एल 350 फुट) के नीचे निर्वासित कुटुम्बों की संख्या, मध्य प्रदेश के 20 ग्रामों में 30 होगी और महाराष्ट्र के 20 ग्रामों में 250 होगी। राजपत्र में अधिकरण के विनिश्चय के प्रकाशन से छह मास के भीतर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपसी परामर्श से, आर एल 106.68 मीटर (आर एल 350 फुट) से नीचे के क्षेत्रों के निर्वासित व्यक्तियों के गुजरात में पुनर्वास के लिए एक या दो पुनर्वास ग्रामों के लिए स्थान तय करेंगे। गुजरात पुनर्वास ग्रामों के लिए आवश्यक भूमि अजित करेगा और अधिकरण के विनिश्चय से दो वर्ष के भीतर उसे उपलब्ध कराएगा। गुजरात में पुनर्वास ग्रामों के स्थानों के विनिश्चय से छह मास के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आर एल 106.68 मीटर (आर एल 350 फुट) से नीचे के क्षेत्रों से गुजरात में प्रवास करने के इच्छुक निर्वासित कुटुम्बों की संख्या गुजरात का सूचित करेंगे। शेष निर्वासित कुटुम्बों के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपने अपने राज्यों में पुनर्वास के लिए भूमि अजित करने की व्यवस्था करेंगे।

IV(2)(ii) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, भूमि अर्जन और निर्वासित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए परांत स्थापनों की स्थापना करेगा। अधिकरण के विनिश्चय से तीन मास के भीतर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक के पास, उन राज्यों में स्थापन और पुनर्वास के खर्च के लिए दो लाख रुपये जमा करेगा जिसका समायोजन वास्तविक खर्च के अधिधारण के पश्चात् लिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अधिकरण के विनिश्चय से छह मास के भीतर आर एल 106.68 मीटर (आर एल + 350 फुट) नीचे के क्षेत्रों के लिए भूमि अर्जन कार्यवाहियों आरम्भ करेंगे और अधिकरण के विनिश्चय से तीन वर्ष के भीतर भूमि, गुजरात

का परिवारजना प्रयोजनों के लिए हस्तांतरित कर देंगे। अधिकरण के विनिश्चय से 18 मास के भीतर, गुजरात भूमि के प्रतिकर हेतु मध्य प्रदेश को 70 लाख रुपये और महाराष्ट्र को 100 लाख रुपये अग्रिम देगा, जिसे वास्तविक व्यय के अवधारण के पश्चात् समायोजित किया जाएगा।

IV (2) (iii) आर एन 106.68 मीटर (आर एन + 350 फुट) से ऊपर के क्षेत्रों में निर्वासित कुटुम्बों के संबन्ध में गुजरात, राजपत में अधिकरण के विनिश्चय के प्रकाशन से छह मास के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उन पुनर्वासि ग्रामों की संख्या और साधारण अवस्थिति का सूचना देगा जिनके अधिकरण के विनिश्चय के अनुसार गुजरात द्वारा स्थापित किए जाने की प्रत्यापना है गुजरात की प्रस्थापना की प्राप्ति से एक वर्ष के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों गुजरात को गुजरात में प्रवास करने के इच्छुक निर्वासित कुटुम्बों की संख्या सूचित करेंगे। तीनों राज्य आपस में विचार विमर्श करते, अधिकरण के विनिश्चय से दो वर्ष के भीतर, गुजरात द्वारा अपने ही राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित पुनर्वासि ग्रामों की संख्या और साधारण अवस्थिति का अवधारण करेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे ग्रामों की संख्या गुजरात को बताएंगे जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले हैं और जिनके लिए गुजरात को क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भुगतान करना होगा।

IV (2) (iv) गुजरात जमाखाना के एक वर्ष पहले प्रत्येक पश्चात्पूर्वी प्रक्रम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उन निर्वासित कुटुम्बों के पुनर्वासि के लिए जो गुजरात में प्रवास के लिए इच्छुक हैं, सिंचाई योग्य भूमि और भवन स्थल अर्जित करेगा और उन्हें उपलब्ध करेगा। गुजरात निर्वासित व्यक्तियों को पहले अपने राज्यक्षेत्र में पुनर्वासित करने की प्रस्थापना करेगा।

IV (3) गुजरात निर्वासित व्यक्तियों का निम्नलिखित अनुदानों और सुख-सुविधाओं का भी उपबन्ध करेगा:—

(क) फिर से बसाने के लिए अनुदान (पुनर्वासि अनुदान)—गुजरात प्रत्येक कुटुम्ब को 750 रु० की राशि जिसमें परिवहन प्रभार भी सम्मिलित है, पुनर्वासि अनुदान के रूप में देगा।

(ख) सहायता अनुदान—इसके अतिरिक्त, गुजरात निम्नलिखित मापमान के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब को सहायता अनुदान देगा:

जहाँ कुल प्राप्त प्रतिकर	सहायता अनुदान
2000 रु० से ऊपर है	कुछ नहीं
2000 रु० और 5000 रु० के बीच है	500 रु० जिसमें से उतनी रकम बटा दी जाएगी जो 500 रु० से ऊपर के प्रतिकर के एक तिहाई भाग के बराबर है।
500 रु० से कम है	500 रु०

(ग) नागरिक सुख-सुविधाएं:

1. 100 कुटुम्बों के लिए, एक प्राथमिक विद्यालय (3 कमरे वाला)
2. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक पंचायत घर
3. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक औद्योगिक
4. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक बीज भंडार
5. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक बाल उद्यान
6. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए, एक ग्राम पोखर
7. प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए, नाभीसहित एक पेयजल कुंआ
8. प्रत्येक कानोनी समुचित स्तर की सड़कों द्वारा मुख्य सड़क से

नहीं होनी चाहिए

9. प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए, एक चबूतरा

10. प्रत्येक निर्वासित कुटुम्ब एक सकाफ की जगह पर 18.29 × 27.43 मी० (60' × 90') माप का एक भूखण्ड—

निष्पत्ति पाने का हकदार होगा और उसे वह आबंटित किया जाएगा। इसके अलावा, नागरिक सुख-सुविधाओं के लिए सड़कों, सरकारी भवनों, खुले स्थानों आदि के लिए 302- अतिरिक्त क्षेत्र की व्यवस्था करेगा।

11. गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वासि के लिए, निम्नलिखित व्यवस्थाएं करेगा:—

	रूप
(क) पुनर्वासि	750 प्रति कुटुम्ब
(ख) सहायता अनुदान	500 प्रति कुटुम्ब
(ग) प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासि के लिए भू-अर्जन जो प्रति 6 कुटुम्ब 0.40 हेक्टर (एक एकड़) को बर मे किया जाएगा	1500 प्रति एकड़
(घ) नागरिक सुविधाएं	
1. 100 कुटुम्बों पर एक प्राथमिक विद्यालय	प्रति विद्यालय 30,000
2. 500 कुटुम्बों पर एक सामुदायिक हाल एवं पंचायत भवन	प्रति भवन 20,000
3. 500 कुटुम्बों पर एक चिकित्सालय	प्रति चिकित्सालय 25,000
4. 500 कुटुम्बों पर एक बीज भंडार	प्रति भंडार 10,000
5. 500 कुटुम्बों पर एक बाल उद्यान	प्रति उद्यान 6,000
6. 50 कुटुम्बों पर नाभी सहित एक कुंआ	प्रति कुंआ 10,000
7. 500 कुटुम्बों पर एक तालाब	प्रति तालाब 20,000
8. 50 कुटुम्बों पर एक छायादार चबूतरा	प्रति चबूतरा 1,500
9. 100 कुटुम्बों पर एक धार्मिक पूजा-स्थल	प्रति पूजास्थल 1,000
10. प्रति नई आबादी के लिए 3 कि०मी० के त्रिभुज से पहुंच मार्गों और संपर्क मार्गों का विनिर्माण	प्रति कि० मी० 30,000
11. विद्युत वितरण लाइनें, और गलियों में रोशनी, प्रति 100 कुटुम्ब 2 कि०मी०	11,000
12. जलप्लावन के अधीन आने वाले प्रत्येक नगरीय कस्बे के लिए सामाजिक सुविधाएं, जैसे, जल प्रशाय और सफाई सुविधाओं का अभियान और समतलन आदि	प्रति कस्बा 5,00,000

IV (4) (i) गुजरात को निवेश दिया जाता है कि वह अपने भूमि प्रतिकर और पुनर्वासि के प्राक्कलन में, इसमें पूर्व उप खण्ड IV (3) में अंतर्निहित निवेशों के अनुसार पुनर्वासि और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करे।

IV (4) (ii) इसमें इसके पूर्व अंतर्निहित उपबंधों के होते हुए भी गुजरात, सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि या पीने के पानी के कुओं, प्राथमिक विद्यालय भवनों, भीतरी सड़कों, ग्राम्य स्थलों, पहुंच मार्गों, चिकित्सालयों, पंचायत भवनों, ग्रामीण विद्युतीकरण, राजमार्गों, कलों, टेलीग्राफ लाइनों, शक्ति लाइनों आदि जैसी सुविधाओं या प्रसुविधाओं की हानि के लिए प्रतिघर का संवाद करने का वादी नहीं होगा, किन्तु यह तब जब उसके स्थान पर वैकल्पिक संपत्ति, सुविधाओं या प्रसुविधाओं की व्यवस्था सरकार सरोह, परियोजना की लागत पर की जानी है। उन पक्षकारों को जिनके नि

मुविधाएं हैं, यह बिकल्प प्राप्त होना कि वे विद्यमान मुविधाओं के लिए प्रतिकर ग्रहण करने या गुजरात के व्यय पर उसे प्रतिस्यापित या स्थानांतरित करा लें।

IV(5) : यह स्पष्ट किया जाता है कि खण्ड IV(3)(ग) के अधीनीय मूल्य, वास्तविक पुनर्वास के समय परिवर्तित हो सकते हैं। यदि परिवर्तित मूल्यांकन के संबंध में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो मामले का अवधारण माध्यस्थता द्वारा, ऊपर खण्ड III(2) में विहित रीति में, किया जाएगा और तदनुसार गुजरात के दायित्व में भी परिवर्तन हो जाएगा।

IV(6)(i) : निष्कासित व्यक्तियों को पुनर्वास देने में गुजरात के असफल होने की दशा में, या निष्कासित व्यक्ति, गुजरात द्वारा प्रवान किए गए क्षेत्र में बसना न चाहते हो तो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऊपर खण्ड IV(1) से (4) में उल्लिखित रीति में पुनर्वास, नागरिक मुविधाओं प्राप्ति की व्यवस्था करेंगे। ऐसी दशा में गुजरात ऐसे सभी व्यय, खर्च प्राप्ति देने के लिए दायी होगा जो उस दशा में गुजरात ऐसे सभी व्ययों, खर्चों प्राप्ति के संबंध के लिए दायी होगा जो निष्कासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और नागरिक मुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में हैं। इसके अन्तर्गत, निवासित व्यक्तियों को खेती करने या आवास के लिए आर्बंटिड भूमि के अर्जन के लिए की गई कार्यवाही का खर्च और भू अर्जन अधिनियम के अनुसार दिए गए प्रतिकर की रकम भी है।

IV(6)(ii) : मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कोई भी क्षेत्र सरदार सरोवर के अधीन तब तक जलप्लावित नहीं किया जाएगा जब तक कि समस्त भूमि और सम्पत्ति के अर्जन के लिए, दिए गए सभी प्रतिकर, किए गए सभी व्यय और लागत का संशय नहीं कर दिया जाता और वहाँ के निष्कासितों के पुनर्वास की व्यवस्था इन निर्देशों के अनुसार कर के निष्कासितों को सूचित नहीं कर दिया जाता।

IV(7) : कृषि भूमि का आर्बंटन :—ऐसा प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब, जिसकी 25 प्रतिशत से अधिक भू-धृति अर्जित कर ली जाती है, सम्बद्ध राज्य में विहित अधिकतम भूमि सीमा और प्रति कुटुम्ब कम से कम 2 हेक्टर (5 एकड़) की सीमा के अधीन रहने हुए, अर्जित भूमि के बराबर विहित भूमि आर्बंटित किए जाने का हकदार होगा। और निम्नार्थ की सुविधाएं, उस राज्य द्वारा दी जाएंगी जिसके राज्य-क्षेत्र के भीतर आर्बंटित क्षेत्र स्थित है यह भूमि विस्थापित कुटुम्ब को, यदि वह चाहे तो, अंतरित कर दी जाएगी। उस के लिए प्रभारित कीमत वह होगी जो गुजरात और सम्बद्ध राज्य के बीच तय की जाएगी। भूमि के लिए, संदस्त की जाने वाली कीमत में से, विस्थापित कुटुम्ब को अर्जित भूमि के प्रतिकर के रूप में उसे दी जाने वाली रकम का 50 प्रतिशत, संदाय की आरम्भिक किस्त के रूप में, गुजरा कर लिया जाएगा। आर्बंटित भूमि की प्रतिशेष रकम आर्बंटिती से 20 वार्षिक किस्तों में व्याज रहित रूप में, वसूल की जाएगी। यदि भूमि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में आर्बंटित की जाती है। और गुजरात उसके लिए भुगतान कर देता है, देखिए खण्ड IV(6)(1), तो आर्बंटित भूमि के लिए सभी बसूलियां गुजरात के खाते में जमा की जाएंगी।

IV(8) : यदि इन निर्देशों के खण्ड IV(1) से (7) तक की बाबत राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह इन निर्देशों के खण्ड III(2) में विहित रीति में माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। माध्यस्थता और वही उसे तय करेगा।

**उपखण्ड V: गुजरात द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को किए जाने वाले संदाय का कार्यक्रम :**

V(1) : गुजरात, अधिकरण का विनिश्चय, राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र सरदार सरोवर परियोजना के लिए अधिकरण द्वारा यथा स्वीकृत उपशीघ्र ख-भूमि का एक नया प्राश्नकत, जिसके अंतर्गत विशिष्टित: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि अर्जन की लागत और विस्थापित कुटुम्बों के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वास की लागत भी होगी, तैयार करेगा और अग्र पक्ष पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत करेगा।

V(2)(i) अधिकरण का विनिश्चय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र और प्रत्येक दशा में, उसके पश्चात् से तीन मास के अन्तराल में पूर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य, गुजरात की अपन-अपने सीमा क्षेत्र के उन सभी तालुकों के जो भागत: या पूर्णत: सरदार सरोवर में जलप्लावित हो सकते हैं, मजमूनी/तालुका नक्शों के तीन-तीन सेट देगे। ये नक्शे ग्राम की सीमा उपदर्शित करेंगे। गुजरात, मजमूनी/तालुका नक्शों की प्राप्ति के पश्चात् से तीन मास के भीतर, उन पर एक-एक एम० एम० से नीचे के क्षेत्रों को एम० एम० एम० एम० एम० एम० एम० डब्ल्यू० एम० के बीच के क्षेत्रों को, जिनके अंतर्गत पञ्जाब से प्रभावित क्षेत्र भी है, चिह्नान्कित करेगा और इस प्रकार चिह्नान्कित करने के पश्चात् एक-एक सेट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को वापस कर देगा।

V(2)(ii) : पूर्वोक्त रूप में चिह्नान्कित मजमूनी/तालुका नक्शों का एक सेट वापस पाने के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र और प्रत्येक दशा में उससे छह मास के भीतर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचनाएं प्रकाशित करेंगी जिनमें यह अधिसूचित किया जाएगा कि उनके सीमा क्षेत्र के भीतर एक-एक एम० एम० से नीचे स्थित भूमि और एक-एक एम० एम० एम० एम० डब्ल्यू० एम० के बीच स्थित भवनों पार्श्वस्थ भूमि सहित, और जो एम० डब्ल्यू० एम० के परिणाम स्वरूप पञ्चाजस से प्रभावित है (अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए), की सरदार सरोवर परियोजना के लिए आवश्यकता पड़ सकती है।

V(2)(iii) : यथापूर्वोक्त राजपत्र में अधिकरण के विनिश्चय के प्रकाशन के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र, और प्रत्येक दशा में उससे एक वर्ष के भीतर गुजरात, बांध के सन्निर्माण के वार्षिक कार्य-क्रम की सूचना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देगा।

V(2)(iv) : अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित भूमि के प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध प्राप्त किसी अप्पत्ति की सुनवाई की जाएगी और उसे निबटया जाएगा और अधिनियम की धारा 5क की उपधारा II(2) के अधीन यथा अप्पत्ति कोई रिपोर्ट राज्य सरकार का शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारें अधिनियम की धारा 6 के अधीन अप्पत्ति अधिसूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र और प्रत्येक दशा में अधिनियम की धारा 4 की उपधारा(1) के अधीन अपनी-अपनी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान से पूर्व, जारी करेंगी।

V(2)(v) : गुजरात से सरदार सरोवर बांध के सन्निर्माण का वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त होने पर, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के परामर्श से, यथा साध्य शीघ्र अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर भूमि के अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनियम देने और अधिनियम की धारा 16 के अधीन भूमि का कब्जा लेने के प्रक्रम तक के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे।

V(3)(i) : गुजरात से अप्पत्ति की जाति है कि वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, उनके द्वारा अनिवार्यत: अर्जित की गई ऐसी भूमि के लिए, जो गुजरात की दी जाती है, प्रतिकर का और गुजरात को दी जाने वाली सरकारी भूमि के बाजार मूल्य का, संदाय करे और ऐसे व्यय का भी संदाय करे जो इनमें इससे पहले उपबधित रूप में निष्कासित कुटुम्बों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वासित करने के संबंध में उगतत किया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को या उससे पूर्व गुजरात को वह रकम सूचित करेंगे जो गुजरात द्वारा क्रमश: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संदस्त की जानी है। ऐसी रकम सूचित करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेंगे, अर्थात्:—(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उस का विस्तार जिसकी बाबत अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिनियम किए जाने है।

(ख) उस सरकारी भूमि का विस्तार अगले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा गुजरात को दी जानी है।

(ग) निष्कासित कुटुम्बों के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वास की बाबत अगले वित्त वर्ष के दौरान उनके पुनर्वास पर मध्य प्रदेश

और महाराष्ट्र द्वारा किया जाने वाला था। अतः वित्त वर्ष के लिए इस प्राकल्पनों को तैयार करने में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उन प्रांतों की शिमा में ले लेंगे जो गुजरात द्वारा इन खण्ड के अनुसंधान में प्राप्त किए गए संसाधन और वस्तुतः उक्त वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश के बीच है।

V(3)(ii): इन प्राकल्पनों के आधार पर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 31 सई की या उस से पूर्व कृषि खण्ड V(3)(i) में तथा उपयोगिता प्राकल्पित रकम का संसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कर देगा।

V(3)(iii): गुजरात, जलप्लावन के प्रत्येक उत्तरवर्ती प्रक्रम पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जलप्लावन के अधीन आने वाले क्षेत्र की सूचना, कम से कम 18 मास पूर्व देगा। जलप्लावन के संबंधित प्रक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्र के निवासी, संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित की जाने वाली ऐसी बारीख तक जो जलप्लावन की बारीख से छह मास से कम पूर्व की नहीं होगी, अपनी संपत्ति को अधिभोग में लेने या उपयोग करने के हवादार होंगे और ऐसे अधिभोग या उपयोग के लिए उन्हें कुछ नहीं देना होगा। उन्हें अधिसूचित बारीख तक क्षेत्र-खाली अवस्था कर देना होगा।

V(4)(i): गुजरात द्वारा प्रतिवर्ष अनिवार्यता: अर्जित की गई पूर्वोक्त भूमि के लिए मध्य प्रदेश की रकम का संसार कर दिए जाने पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की धारिणीध, अर्जन पूरा करने और वह भूमि गुजरात को अंतरित कर देंगे जिससे कि वह भूमि, इन निदेशों के खण्ड V(5) से (8) तक के अधीन रहते हुए, केवल जलप्लावन के प्रयोजनों के लिए, गुजरात में निहित हो जाए।

V(4)(ii): इस में इनके पूर्व उपबंधित रूप में गुजरात द्वारा सरकारी भूमि का बाजार मूल्य संश्लेष कर दिए जाने पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा भारत संघ ऐसी भूमि गुजरात को सौंप देंगे, जिसे जिससे कि वह भूमि, इन निदेशों के खण्ड V(5) से (8) तक के अधीन रहते हुए, केवल जलप्लावन के प्रयोजनों के लिए, गुजरात में निहित हो जाए।

(5) गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तत्संबंधी भूमि राजस्व संहिताओं के अनुसार गुजरात के लिए अर्जित या उसे हस्तांतरित तत्सम्बन्धी राज्यक्षेत्रों में भूमि के लिए प्रतिवर्ष सदैव भू-राजस्व की रकम, क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समय-समय पर विद्यमान वर्गों से, संसार करेगा।

(6) यथास्थिति, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात को प्रत्येक वर्ष ऐसा कोई राजस्व जो उन भूमियों पर खेती करने से प्राप्त हो, जो सरदार सरोवर में कामिकत: उच्छलन हो जाए, उसमें से उसके संग्रहण प्रक्रमों की कटौती करने के पश्चात्, प्रेषित करेगा।

(7) जलप्लावन के अधीन आने वाली भूमि के गुजरात में निहित हो जाने पर भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जलप्लावन क्षेत्र पर अपने-अपने राज्य में अपनी संग्रहण के अधिकार का प्रयोग करने रहेंगे।

(8) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः अपनी-अपनी जल प्लावन भूमि पर, झील के एक भाग में सखली पकड़ने, नौबानन और जलपरिवहन के अधिकारों का अन्यथा रूप से प्रयोग करने के हकदार होंगे परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकार का प्रयोग सरदार सरोवर परियोजना की किसी उपयोगिता, पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले या परियोजना कामिको के विधिपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न न करे।

(9) जल प्लावन के अधीन आने वाली भूमि के ऐसे अवशिष्ट अधिकांश जो विनिर्दिष्ट रूप से गुजरात की अंतर्गत नहीं किए गए हैं, उस प्रकार में निहित बने रहेंगे जिसके सीमा क्षेत्र में वे स्थित हैं।

V(10): उक्त भूमि के जलप्लावन के प्रयोजनों के लिए, जिसके लिए उसे अर्जित किया गया है, उपयोग न किए जाने की दशा में, गुजरात

राज्य यथास्थिति, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र को ऐसी भूमि इन प्रांतों के अधीन रहते हुए पुनः अंतरित कर देगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसी भूमि को भारत गुजरात में प्राप्त प्रतिकर को रकन बाजार कर देंगे।

V(11): यदि निर्वसित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए अर्जित किया भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है तो जहाँ संभव है, संसार किए जाने पर उसे मूल स्वामी को वापस दिया जाएगा या अन्यथा निवृत्त दिया जाएगा और प्राप्ति गुजरात के खाते में जमा कर दी जाएगी।

V(12): सरदार सरोवर की वास्तविक भूमि अर्जित करने और निर्वसित व्यक्तियों के पुनर्वास पर गुजरात द्वारा किए गए सभी खर्च, सरदार सरोवर परियोजना प्राकल्पन, यूनिट 1 बांध और अनुसंधान संकर्म पर प्रभावित किया जाएगा।

खण्ड VI: यदि सभी प्रकार राज्य करार द्वारा सभी पूर्ववर्ती खण्डों या उनमें से किसी में कोई परिवर्तन, संशोधन और उपांतरण करने हैं तो खण्ड XI को कोई बात उसे निवारित नहीं करेगी।

खण्ड XII: सरदार सरोवर परियोजना के खर्च का सिवाई और शक्ति विभाग के बीच बांंटन

इस अवधारित करने है कि यूनिट 1-बांध और अनुसंधान संकर्म का खर्च सिवाई और शक्ति विभाग के बीच निम्नानुसार बांटा जाएगा—

सिवाई विभाग	43.9 प्रतिशत
शक्ति विभाग	56.1 प्रतिशत

खण्ड XIII: सरदार सरोवर परियोजना के खर्च के सिवाई भाग का गुजरात और राजस्थान के बीच बांंटन

(क) (1) सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट 1 (बांध और अनुसंधान संकर्म) के खर्च में सिवाई भाग को गुजरात और राजस्थान के बीच 18:1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(क) (ii) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपने राज्यक्षेत्रों में प्रयोग के लिए सरदार सरोवर से लिए जाने वाले जल के लिए सरदार सरोवर बांध की लागत के सिवाई संघटक और उसके प्रचालन और वाचिक अनुसंधान के आनुपातिक अंश का भी अभिदाय करेगा। आनुपातिक अंश 9.5 फुट 0.00 फुट में से लिए जाने वाले जल की मात्रा के अनुपात में होगा। इस प्रकार अभिदाय की जाने वाली रकम, गुजरात और राजस्थान के खाते में 18:1 के अनुपात में जमा की जाएगी।

(ख) नर्मदा निर्वहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नवगांव नहर और उसके विज्ञान की लागत दोनों राज्यों द्वारा निम्नलिखित रूप में बांटी जाएगी:

(i) गुजरात द्वारा प्रस्तावित ग्रेडिएण्ट के लिए भूमि भू-कार्य और साइनिंग की बाबत लागत अन्तर और जो अब विहित है, पूर्ण रूप से गुजरात वहन करेगा।

(ii) नहर की वास्तविक लागत से ऊपर (i) को कम करके जो बांटा जाएगा, वह अप्रैक मोल के आधार पर बांटा जाएगा।

वास्तविक लागत को गुजरात और राजस्थान के बीच पहले अप्रैक मोल आधार पर बांटा जाएगा और कार्य समाप्त हो जाने पर लागत का अंश ऊपर बताए गए अनुसार समायोजित किया जाएगा। राजस्थान अपने हिस्से की लागत प्रति वर्ष बजट ब्रांडन के आधार पर जमा करेगा। इसे बाद में वर्ष के अन्त में वास्तविक खर्च के अनुसार समायोजित किया जाएगा। अनुसंधान पर सक्षमण के पश्चात् खर्च को सक्षमण के खर्च के रूप में नहीं माना जाएगा।

यदि लागत बांटने के प्रयोजनार्थ नवगांव मुख्य नहर की बाबत खर्च के बांंटों पर राजस्थान और गुजरात के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो विचार नर्मदा निर्वहन प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे निर्देश पर उसका विनिर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।



**खण्ड 14: अधिकरण के विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तंत्र की स्थापना**

हम, प्राधिकरण के विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तंत्र की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

**उपखण्ड 1: प्राधिकरण का गठन**

1(1) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें भागे आदेश कहा गया है) के विनिश्चयों और निर्देशों का पालन और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जिसे इसमें भागे प्राधिकरण कहा गया है) नामक एक अंतरराज्यिक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।

1(2) प्राधिकरण में सात उच्च पंक्ति के इंजीनियर होंगे, जिनमें से हर एक सिविल विभाग, शक्ति विभाग या राज्य विद्युत बोर्ड का प्रमुख इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर या अपर मुख्य इंजीनियर होगा और जिन्हें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीन अन्य प्रख्यात इंजीनियर होंगे, जो मुख्य इंजीनियर से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे और जिन्हें केन्द्रीय सरकार पक्षकार राज्यों से परामर्श करके नियुक्त करेगी। तीन स्वतंत्र सदस्यों में से एक को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उसे उन अधिवेशनों में, जहाँ एक से अधिक राज्यों के हित पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर विनिश्चय किया जाता हो, विमर्शी मद प्राप्त होगा और वह प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्य का भारमाधक होगा। यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसे किसी सदस्य को, जो उसकी राय में सदस्य के रूप में जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, प्राधिकरण से हटाने या निलम्बित करने की शक्ति होगी।

1(3) प्रत्येक स्वतंत्र सदस्य पूर्ण कालिक सदस्य होगा और अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायगा। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सदस्य अर्ध-कालिक सदस्य होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी ही, यथास्थिति, स्वतंत्र सदस्य या अर्धकालिक सदस्य के लिए नियुक्ति के निवृत्तन और शर्तें अवधारित करेगा। प्राधिकरण के सात सदस्यों की प्रथम नियुक्ति, अधिकरण के विनिश्चय के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से यथासाध्य तीन मास के भीतर कर दी जाएगी।

**1(4) सदस्यों के रिक्त स्थान**

यदि तीन स्वतंत्र सदस्यों में से किसी का स्थान रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और स्वतंत्र सदस्यों से भिन्न चार सदस्यों में से कोई स्थान रिक्त हो जाने पर, राज्य सरकार जिसके द्वारा वह सदस्य जिसका पद रिक्त हुआ है, नियुक्त किया गया था, उक्त रिक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

किसी सदस्य की बीमारी या किसी भी कारण अनुपस्थिति की दशा में, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार (यथास्थिति), जिसके द्वारा वह नियुक्त किया था, ऐसी बीमारी या अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति को स्थानापन्न सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसे स्थानापन्न सदस्य को इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करते हुए, उस सदस्य की (देखिए उपखण्ड 5) जिसके धकेले में वह इस प्रकार कृत्यशील है, सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और क्षतिपूर्ति का हकदार होगा। किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भगला अर्ध स्वतंत्र सदस्य, न कि स्थानापन्न सदस्य प्राधिकरण के कारवारी अधिवेशनों में अध्यक्ष के रूप में या प्राधिकरण के अध्यक्ष के बीमार होने या अनुपस्थिति होने की दशा में, अध्यक्ष के रूप में, कार्य करेगा।

957GJ/19—2

**उपखण्ड 2: प्राधिकरण का सचिव:**

प्राधिकरण एक सचिव नियोजित करेगा जो इंजीनियर होगा। वह प्राधिकरण का सबसे नहीं होगा।

**उपखण्ड 3: गणपूर्ति और सतधान**

प्राधिकरण के ऐसे कारबार के सिवाय जिसे प्राधिकरण नेमी रूप में समय-समय पर विहित करे सभी अन्य कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी और बहुमत की महमति आवश्यक होगी। प्राधिकरण ऐसे किसी कारबार को, जिसमें किन्ही दो राज्यों के हितों में विरोध होने की संभावना हो, नेमी के रूप में विहित नहीं करेगा। नेमी कारबार के संव्यवहार के लिए तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी और प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अधिवेशन में निर्वाचित अध्यक्ष को विमर्शी मत प्राप्त होगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत भी प्राप्त होगा।

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए सदस्यों को समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

**उपखण्ड 4: प्राधिकरण द्वारा कार्य का निपटान**

4(1) नीचे उपखण्ड 4(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी अपने समक्ष कार्य का निपटान परिपत्र द्वारा या अधिवेशन बुलाकर कर सकेगा। तथापि, प्राधिकरण का कोई सदस्य यह अपेक्षा कर सकेगा कि प्रभूक कार्य का निपटान परिपत्र द्वारा न करके अधिवेशन में किया जाए।

4(2) प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर अपना विनिश्चय किसी अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष और पक्षकार राज्यों के सदस्य उपस्थित हों, संकल्प द्वारा अभिलिखित करेगा:—

(1) कारबार संबंधी नियमों की रचना;

प्राधिकरण के किसी सदस्य या सचिव अथवा किसी पदाधिकारी को कृत्यों का प्रयायोजन;

(3) प्राधिकरण के कारबार के किसी भाग का औपचारिक या नेमा प्रकृति के कारबार के रूप में वर्गीकरण;

(4) कोई अन्य ऐसा विषय जिसके विनिश्चय की बात चार पक्षकार राज्यों में से कोई यह अपेक्षा करे कि वह किसी ऐसे अधिवेशन में किया जाए जिसमें पक्षकार राज्यों के सभी सदस्य उपस्थित हों।

किन्तु यदि इस उपखण्ड के अधीन किसी विनिष्ट मद का दो क्रमवर्ती बैठकों में पक्षकार—राज्यों में से किसी एक या अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो उसका निपटारा खण्ड 14 के उपखण्ड 3 के अधीन किया जायगा।

4(3) पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण अपने कारबार के संचालन के लिए अपने नियम बनाएगा।

4(4) प्राधिकरण, अपनी समस्त कार्यवाहियों का समुचित कार्यवृत्त या अभिलेख स्थायी अभिलेख के रूप में रखाएगा।

**उपखण्ड 5: सदस्यों का परिवर्तन**

निम्नलिखित से उत्पन्न हानि, क्षति या नुकसान के लिए प्राधिकरण का कोई भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा, अर्थात्

(क) ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सम्भावपूर्वक और बिना विरोध के स्पष्ट आदेश के प्राधिकार के अधीन की गई कोई कार्रवाई, भले ही बाद में ऐसी कार्रवाई को अप्राधिकृत अवधारित कर दिया जाए, या

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियोजित और ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के अधीन सेवारत किसी अन्य व्यक्ति का उपेक्षापूर्ण या दोषपूर्ण कार्य या लोप, किन्तु यह तब जब कि ऐसा सदस्य अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे अन्य व्यक्ति की नियुक्ति में या उसके कार्य के पर्यवेक्षण में सम्यक् सावधानी बरतने में असफल न रहा हो।

#### अपखण्ड 6: प्राधिकरण के अधिकारी और सेवक

प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे और उतने अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकता है, जो वह ठीक समझे और उन्हें उन नियमों और विनियमों के अधीन सेवा से हटा सकता है या पदच्युत कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के संबंध में लागू होते हैं। ऐसे सभी अधिकारी और सेवक एकमात्र प्राधिकरण के नियंत्रण में होंगे। बेतत्मान और सेवा की अन्य बातें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होती हैं। उक्त चारों राज्यों की सेवा में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति या नियोजन प्राधिकरण उस अनुपात में कर सकेगा जो वह ठीक समझे। प्राधिकरण राज्य सरकारों से ऐसी व्यवस्था करेगा कि वे राज्य सरकारों में नियोजित व्यक्तियों को प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन के लिए या प्राधिकरण के लिए किसी कार्य या सेवा को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध करें। प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को सीधे भर्ती भी कर सकेगा या केन्द्र से भर्तियाँ किसी अन्य स्रोत से, जो भी वह उपयुक्त समझे, ऐसा व्यक्ति अधिप्राप्त कर सकेगा।

#### अपखण्ड 7: प्रशासनिक और फील्ड संगठन ऋच

प्राधिकरण का समस्त व्यय (जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र सदस्यों के वेतन और व्यय भी हैं) मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य समान अंशों में वहन करेंगे। किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य से संबंधित व्यय, सम्बद्ध राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में गेजों और अन्य जलयोज स्थानों के अनुरक्षण, प्रचालन और नियंत्रण का ऋच और आंकड़ें संसूचित करने के लिए दूर संचार का ऋच सम्बद्ध सरकार वहन करेगी।

भंडारों, शक्ति संस्थानों, मोड़ संकर्मों, शीर्ष संकर्मों और नहरों के सन्निर्माण तथा अनुरक्षण का ऋच पूर्णतः उन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसके क्षेत्र में संकर्म स्थित हैं जहाँ इस प्रकार पूँजी लागत बाँटी जाती है वहाँ प्रचालन और अनुरक्षण लागत भी उसी अनुपात में बाँटी जाएगी और लाभ में बँटवारा होने की दशा में अन्य राज्यों के बीच उसे बाँट दिया जाएगा।

(2) उन संकर्मों को छोड़कर जिनकी लागत दो या अधिक पक्षकार राज्यों के बीच बाँटने का अधिकरण ने निवेश दिया है।

#### अपखण्ड 8: प्राधिकरण की शक्तियाँ, और कर्तव्य :

8(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्य समन्वय और निदेशन करना है। सामान्यतः सभी द्विपक्षीय विषयों का निपटारा सम्बद्ध राज्यों द्वारा मिल-कर करना चाहिए और प्राधिकरण का तभी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जब कोई विवाद हो।

8(2) प्राधिकरण की यह शक्ति और कर्तव्य होगा कि वह ऐसा कोई या सभी कार्य करें जो निम्नलिखित की बाबत आदेशों को लागू करने के संबंध में आवश्यक, पर्याप्त या समीचीन हैं, अर्थात् :—

- (i) नर्मदा जल का भण्डारण, बँटवारा, विनियम और नियंत्रण;
- (ii) सरदार सरोवर परियोजना से प्राप्त शक्ति का बँटवारा;
- (iii) मध्य प्रदेश द्वारा जल का नियमित रूप से छोड़ा जाना;
- (iv) सम्बद्ध राज्य द्वारा सरदार सरोवर के अधीन जलमग्न होने वाली भूमि और सम्पत्तियों का सरदार सरोवर परियोजना के लिए अर्जन;
- (v) निष्कासित व्यक्तियों को प्रतिकर, उनका पुनर्वास तथा व्यवस्थापन; और
- (vi) ऋच का बँटवारा।

8(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अन्य कृत्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्य भी करेगा :—

- (i) यथास्थिति, मध्य प्रदेश या गुजरात प्राधिकरण को, सरदार सरोवर परियोजना रिपोर्ट, नर्मदा सागर परियोजना रिपोर्ट, आकारेश्वर परियोजना रिपोर्ट और महेश्वर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण सम्बद्ध राज्यों, केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग की इन परियोजनाओं की ऐसी कोई विशिष्टता बताएगा जो प्राधिकरण के आदेशों के क्रियाव्ययन के प्रतिकूल हैं। कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन या बाँध, विद्युत-गृहों और नहर शीर्ष संकर्मों को प्रमुख विशेषताओं या सागत में महत्वपूर्ण बूझ प्राधिकरण को सूचित की जाएगी जिससे कि प्राधिकरण उस संबंध में समुचित कार्रवाई कर सके।
- (ii) प्राधिकरण निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, नर्मदेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना का इस-उद्देश्य से चरण क्रम विनिश्चित करेगा और उनके सन्निर्माण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करेगा जिससे कि परियोजनाओं के सन्निर्माण कार्य के पूर्ण होने के दौरान और उसके पश्चात, समीचीन रूप में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।
- (iii) प्राधिकरण, सम्बद्ध राज्यों से, कार्य और व्यय दोनों की बाबत कालिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परियोजना के विभिन्न एककों के सन्निर्माण का प्रगति का पुनर्विवांकन करेगा और जब भी आवश्यक हो, सम्बद्ध राज्य को एकक I—बाँध और अनुलग्न संकर्म तथा एकक III—सरदार सरोवर परियोजना विद्युत काम्प्लेक्स को छोड़कर ऐसे उपाय करने को सलाह देगा जिससे कि कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके। राज्य परियोजनाओं के संबंध में, अपखण्ड 8(3)(i) के अनुसार प्राधिकरण को कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (iv) प्राधिकरण, जब भी आवश्यक हो, सम्बद्ध राज्यों को समुचित निवेश देगा कि वे, गुजरात राज्य के लिए सरदार सरोवर परियोजना में जलमग्न होने वाली भूमि और सम्पत्ति अर्जन करने और तत्पश्चात वे गुजरात राज्य को उपलब्ध कराने और तद्बोधित निष्कासित व्यक्तियों के लिए प्रतिकर और पुनर्वास के संबंध में न्यायाधिकरण के आदेशों का समय से और पूर्णतः अनुपालन करें।

- (5) प्राधिकरण, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक से, जहाँ आवश्यक हो, स्वचालित अभिलेखों से मुमकिन ऐसे प्रवाह और अन्य गेज स्टेशन निकास, गांव और बाष्पीकरण संशोधन स्टेशनों और आदेशों के उपबन्धों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अभिलेख रखने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक माप-युक्तियों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रवर्तन करवाएगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो सम्बद्ध राज्य से मुख्य नहरों के छोर पर और नर्मदा नदी तंत्र से राजस्थान के लिए प्रवाहित जल की मात्रा के मापने के लिए नहर के उप-निकास पर अनुमानित किस्म की माप युक्तियों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रवर्तन करवाएगा।
- (6) नर्मदा के बहाव का उन सभी स्टेशनों पर, जहाँ प्राधिकरण आवश्यक समझें, समवर्ती अभिलेख रखा जाएगा और ऐसे अभिलेखों को सहुसम्बद्ध किया जाएगा।
- (7) प्राधिकरण, इस रिपोर्ट के अड्डा II में दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर जल के लेखा संबंधी नियम या विनियम बनाएगा यह जल के विनियमन और लेखा के प्रयोजन के लिए इस दिन की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य के जल का हिस्सा अवधारित करेगा।
- (8) प्राधिकरण, निम्नलिखित की बाबत अधिकरण के आदेशों का क्रियाम्वयन सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—
  - (क) मध्य प्रदेश द्वारा नियमित रूप से छोड़े जाने वाले जल की मात्रा और स्वरूप;
  - (ख) ऐसे नियमित जल प्रवाह के लिए संदाय/लागत का बंटवारा।
- (9) प्राधिकरण सम्बद्ध राज्य से प्रत्येक मौसम में नर्मदा से सिंचित क्षेत्रों का, नर्मदासागर पर और उसके अधीमुखी जल विद्युत शक्ति स्टेशनों में से प्रत्येक द्वारा उत्पादित शक्ति, घरेलू, नागरीय और औद्योगिक या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए खपत और सरदार सरोवर परियोजना से आगे नदी में जाने वाले जल के आंकड़े एकत्र करेगा।
- (10) प्राधिकरण, नर्मदा या उसकी सहायक नदियों में किसी जल वर्ष (1 जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून तक) में बहने वाले पानी की भांदा अवधारित करेगा।
- (11) प्राधिकरण समय-समय पर प्रत्येक राज्य, द्वारा अपने जलाशयों और अन्य भण्डारों में भंडारित पानी की मात्रा अवधारित करेगा और उस प्रयोजन के लिये कोई भी युक्ति या पद्धति अपना सकेगा।
- (12) प्राधिकरण, राज्यों द्वारा या यथा आवश्यक उनमें से कुछ के द्वारा किसी भी स्थान पर या किसी भी क्षेत्र में तथा किसी भी समय नर्मदा नदी के जल के उपयोग को, समुचित कालिक अन्तरालों पर अवधारित करेगा और इस प्रयोजन के लिये नर्मदा नदी में से या उसकी सहायक नदियों में से सभी विषयनों या शक्यताओं को, चाहे वे प्रकृति हों या कृत्रिम या भागसः प्राकृतिक हों और भागसः कृत्रिम, ध्यान में लेगा और ऐसे उपयोग की ऐसी पद्धति से नापेगा जो वह ठीक समझे।
- (13) प्राधिकरण या मध्यक रूप से प्राधिकृत उनके किसी प्रतिनिधि को ऐसी किसी भूमि या सम्पत्ति पर प्रवेश करने की शक्ति होगी जिस पर नर्मदा जल के प्रयोग के लिय किसी राज्य द्वारा किसी परियोजना या किसी परियोजना का विकास कार्य या गेजिंग बाधन या जलोद स्टेशन के किसी कार्य का या मापक युक्ति

का सन्निर्माण किया गया है या किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य अपने समुचित विभागों द्वारा प्राधिकरण को और इस निमित्त उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को पूर्ण सहयोग और सहायता देगा।

- (14) प्राधिकरण यथा आवश्यक रूप में अधिवेशन करता रहेगा और उनमें उचित जल व्यवस्था की बाबत विनिश्चय करेगा। इसके अन्तर्गत, विशिष्टतः आदेशों के अनुसार नर्मदा नदी प्रणाली के जलाशयों से जल की निकासी की रीति और ब्यौरे भी हों। विशिष्टतः प्राधिकरण पाती भरण मौसम के अन्त में अधिवेशन करेगा और नर्मदा नदी प्रणाली के जलाशयों में जल की उपलब्धता का पुनर्विलोकन करेगा और पिछले भण्डार को ध्यान में रखते हुए अगले सिंचाई मौसम के लिये उनके विनियमन के तरीके की बाबत विनिश्चय करेगा।
- (15) प्राधिकरण, सरदार सरोवर से तीन राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को आर्षित शक्ति के अंशों की पूर्ति में शक्ति के उत्पादन और परेषण के लिये सन्निर्माण के चरण बढ़ कार्यक्रम के लिये तथा उनके लिये संदायों के लिये अधिकरण के आदेशों के अनुसार निदेश देगा। प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरदार सरोवर प्रक्षेत्र में शक्ति का उत्पादन और परेषण आदेशों के अनुसार हो रहा है।
- (16) प्राधिकरण, बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान और बाढ़ नियंत्रण, जिसके अंतर्गत गंभीर अवक्षेपण और तूरसंचार पद्धतियाँ भी हैं, संबंधी कारगर स्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिये समेचित निदेश जारी करेगा। किसी संरचना की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संरचना के भारसाधक मुख्य इंजीनियर पर होगा और उस पर ऐसा कोई विनिश्चय या आदेश बाबत कर नहीं होगा जिसके उसकी राय में, ऐसी संरचना के सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्राधिकरण, बाढ़ों के दौरान जलाशयों के प्रचालन के बारे में प्रतिवर्ष आंकड़े प्रकाशित करेगा और वे पक्षकार राज्यों को उपलब्ध कराएगा।

8(4)—प्राधिकरण, अपने अनुभव के आधार पर, एक संकल्प द्वारा उपरोक्त उपखण्ड 8(3)(1) से (16) तक में प्रगणित कृत्यों में परिवर्तन या वृद्धि कर सकेगा।

8(5) सभी सम्बद्ध राज्य, प्राधिकरण को नर्मदा घाटी विकास से संबंधित और प्राधिकरण द्वारा मांगी जाने वाली सभी सुसंगत जानकारी शीघ्र और मुक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

#### उपखण्ड 9 : प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्टें

प्राधिकरण चारों राज्यों में से प्रत्येक को, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में वर्तमान जल वर्ष (1 जुलाई, से 30 जून तक) की समाप्ति से पूर्व एक वार्षिक रिपोर्टें तैयार कराकर भेजेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण द्वारा किए गए क्रियाकलाप का उल्लेख होगा और प्रत्येक राज्य को, किसी भी समय उसकी प्रार्थना पर, ऐसी कोई जानकारी, जो उसके पास है, उपलब्ध कराएगा और अपने अभिलेखों तक राज्यों और उनके प्रतिनिधियों को पहुँच होने देगा।

#### उपखण्ड 10 : प्राधिकरण का अभिलेख और उसका स्थान

प्राधिकरण सभी अधिवेशनों और कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा, नियमित लेखा रखेगा, और उसका एक ऐसा उपयुक्त कार्यालय होगा जहाँ दस्तावेज, अभिलेख, लेखा और गेजिंग आंकड़े चारों राज्यों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा, ऐसे समयों पर और ऐसे विनियमों के अधीन जैसे प्राधिकरण अवधारित करे, निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

नमंदा नियंत्रण प्राधिकरण के केन्द्रीय, प्रादेशिक और उप प्रादेशिक कार्यालयों का स्थान प्राधिकरण अध्यापित करेगा।

प्राधिकरण के मुख्यालय, जब तक वह स्थायी अवस्थान का विनिश्चय नहीं कर लेता, नई दिल्ली में होंगे।

#### उपखण्ड 11: संविदाएं और करार

प्राधिकरण ऐसी संविदाएं और करार करेगा जो उसे प्रयत्न या उस पर अधिरोपित कृत्यों के पूर्णतः और समुचित निर्वहन के लिये आवश्यक और अनिवार्य हैं।

#### उपखण्ड 12: वित्तीय उपबंध

(1) प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित सभी पूंजीगत और राजस्व व्यय मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य समान रूप से वहन करेंगे। चारों राज्यों की सरकारें, प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित सभी पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए निधि देगी।

(2) प्राधिकरण के गठन के पश्चात् चारों राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार प्रारम्भ में, प्राधिकरण की निधि में 5,00,000 रु० (पांच लाख रुपए) का अभिदाय करेगी।

(3) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास में, पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले आगामी वर्ष के बारह मास के दौरान अपेक्षित धन राशि के वीरेवार प्राक्कलन तैयार करेगा। इन प्राक्कलनों में वह रीति दशिन की जाएगी, जिसमें ऐसा धन खर्च करने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण 15 अक्टूबर को या उससे पूर्व, ऐसे वीरेवार प्राक्कलन की एक-एक प्रति चारों राज्यों के सम्बद्ध मुख्य इंजीनियरों को प्रेषित करेगा और उसमें वह राशि दशित करेगा जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अभिदाय के लिए अपेक्षित है। प्रत्येक राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा दशित रूप में अपने अभिदाय का, प्राधिकरण को संदाय आगामी वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पूर्व कर देगा।

(4) प्राधिकरण सभी प्राप्तियों और संवितरणों का ब्योरा और सही लेखा रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और उसकी प्रतियां सम्बद्ध महालेखाकारों तथा चारों राज्यों के सम्बद्ध मुख्य इंजीनियरों को भेजेगा। वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप ऐसा होगा जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए। प्राधिकरण द्वारा रखा गया लेखा, चारों राज्यों के प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(5) प्राधिकरण की निधि से संवितरण ऐसी रीति से किए जाएंगे जैसा प्राधिकरण विहित करे, प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी आपात में ऐसा खर्च कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) प्राधिकरण द्वारा रखे गए लेखाओं की लेखा परीक्षा, भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या उसका नामनिर्देशित करेगा जो प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं का ऐसे संवेक्षणों के अधीन रहते हुए जैसे वह करना चाहे, प्रमाणित करेगा, प्राधिकरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

की रिपोर्ट की प्रतियां, महालेखाकार और चारों राज्यों के सम्बद्ध मुख्य इंजीनियरों को भेजेगा तथा उसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेगा।

#### उपखण्ड 13: प्राधिकरण का विनिश्चय

उपखण्ड 8 के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों की बाबत प्राधिकरण के विनिश्चय अन्तिम और चारों राज्यों पर बाबद कर होंगे। किन्तु, एक पुनर्विलोकन समिति होगी जो स्वयंसेवा से या किसी पक्षकार-राज्य के आवेदन पर, प्राधिकरण के किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगी, अत्यावश्यक मामलों में, पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष, पक्षकार राज्य के आवेदन पर, पुनर्विलोकन में अन्तिम विनिश्चय होने तक प्राधिकरण के किसी आदेश के निष्पादन को रोक सकता है।

#### उपखण्ड 14: पुनर्विलोकन समिति

14(1) पुनर्विलोकन समिति में अध्यक्ष सहित निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे :—

- (i) केन्द्रीय सिव्वाई मंत्री—अध्यक्ष
- (ii) मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश—सदस्य
- (iii) मुख्य मंत्री, गुजरात—सदस्य
- (iv) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र—सदस्य
- (v) मुख्य मंत्री, राजस्थान—सदस्य

केन्द्रीय कृषि और सिव्वाई मंत्रालय, सिव्वाई विभाग का सचिव, पुनर्विलोकन समिति का संयोजक होगा किन्तु उसे महाधिकार प्राप्त नहीं होगा।

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने की दशा में, उस राज्य का राज्यपाल या उसका प्राधिकृत प्रांतनिधि, पुनर्विलोकन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

14(2) चारों राज्यों के मुख्य मंत्री, अपने-अपने सिव्वाई मंत्रियों को वैकल्पिक सदस्य के रूप में या तो साधारणतया या विशेष रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकेंगे ऐसे मंत्रियों को महाधिकार, विनिश्चय आदि करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।

14(3) पुनर्विलोकन समिति, प्राधिकरण के विनिश्चय का ऐसे किसी अधिवेशन में पुनर्विलोकन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष तथा पुनर्विलोकन समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं। यह आशा की जाती है कि पुनर्विलोकन समिति के सभी विनिश्चय सर्वसम्मति से होंगे। सर्वसम्मति से न हो पाने की दशा में वे सदस्यों के जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, बहुमत से किए जाएंगे।

14(4) संयोजक पुनर्विलोकन समिति के प्रस्तावित अधिवेशन की अग्रिम सूचना, उसकी कार्यसूची और कार्यसूची टिप्पण, पक्षकार राज्यों को भेजेगा।



14(5) पुनर्विलोकन समिति का विनिर्णय, लेखबद्ध किया जाएगा और वह अन्तिम तथा सभी राज्यों पर बाधकार होगा।

#### उपखण्ड 15: प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर सन्निर्माण

खण्ड XIV के उपखण्ड 16 में विहित सीमा को छोड़कर और उनके सिवाय, परियोजनाओं का आयोजन और सन्निर्माण प्रत्येक राज्य, अपने अधिकारों के माध्यम से कराएगा।

#### उपखण्ड 16 : सरदार सरोवर परियोजना पर प्राधिकरण के पर्यवेक्षी कृत्य

(1) एकक I—सरदार सरोवर परियोजना के बांध और अनुलग्न संकर्म की वाहन चारों पक्षकार राज्य वित्तीय रूप में प्रतिबद्ध हैं उनमें से तीन, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एकक III—परियोजना के शक्ति प्रोजेक्ट की वाहत ऐसे ही प्रतिबद्ध हैं। परियोजना के इन एककों के तत्परतापूर्वक, मितव्ययितापूर्ण और भीषणनिष्पादन के लिए और पक्षकार राज्यों की वित्तीय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, यह यांचनीय और आवश्यक है कि इन प्रयोजन के लिए एक सन्निर्माण सलाहकार समिति गठित की जाए।

अतः हम यह आदेश करते हैं कि सरदार सरोवर सन्निर्माण सलाहकार समिति नामक एक सलाहकार समिति का गठन, राजपत्र में अधिकरण के विनिर्णय के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर, किया जाए।

(2) सन्निर्माण सलाहकार समिति का एक पूर्णकालिक सचिव होगा जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति का होगा तथा जिसकी नियुक्ति भारत संघ द्वारा की जाएगी। समिति में तथाप्यक्त अन्य कार्यवाह्य होंगे।

(3) समिति में निम्नलिखित भी होंगे :—

(i) भारत सरकार में सिवाई का भारसाधक सचिव—अध्यक्ष।

(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (के० ज० आ०) या यदि अध्यक्ष अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए के० ज० आ० का कोई सदस्य।

(iii) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) या यदि अध्यक्ष अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए के० वि० प्रा० का कोई सदस्य।

(iv) अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (न० नि० प्रा०) या यदि अध्यक्ष अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए न० नि० प्रा० का कोई स्वतंत्र सदस्य।

(v) संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) कृषि और विवाई मंत्रालय, भारत सरकार (सिवाई विभाग)।

(vi) मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के वित्त विभाग के भारसाधक सचिव।

(vii) गुजरात और राजस्थान राज्यों के कृषि विभाग के भारसाधक सचिव।

(viii) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विद्युत विभाग के भारसाधक सचिव।

(ix) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राजस्व विभागों या भूमि अर्जन में सम्बन्धित अन्य विभाग के भारसाधक सचिव।

(x) गुजरात राज्य में परियोजना का भारसाधक महाप्रबंधक या मुख्य इंजीनियर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के परियोजना में सम्बद्ध मुख्य इंजीनियर।

(xi) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष।

(xii) जिनके सलाहकार, सरदार सरोवर परियोजना किसी विशिष्ट अधिवेशन के लिए अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकेंगे।

(4) सरदार सरोवर सन्निर्माण सलाहकार समिति :—

(i) इन संकर्मों के लिए तैयार किए गए परियोजना प्राकृतनों की संवीक्षा करेगी, आवश्यक उपकरण करने का सुझाव देगी और सम्बद्ध सरकारों के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्राकृतनों की निष्कारिण करेगी ;

(ii) तकनीकी विशेषताओं और डिजाइनों के संबंध में सभी प्रस्तावों की, जो उस किसी पक्षकार राज्य द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, परीक्षा करेगी और निष्कारिण करेगी और जहां भी आवश्यक हो इन प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करेगी ;

(iii) उक्त निधि, परियोजना की आवश्यकता और जोष परिणाम प्राप्त करने की यांचनीयता को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के विभिन्न भागों के सन्निर्माण के कार्यक्रम की समन्वित रीति से जांच करेगी और उस बाजब सिकारिण करेगी ;

(iv) अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार संकर्म के सन्निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए निधि की प्रयोज्यता की जांच करेगी और आवश्यक सिकारिण करेगी ;

(v) समय-समय पर ऐसी तकनीकी और वित्तीय शक्तियों के, जिन्हें यह परियोजना के सक्षम निष्पादन के लिए आवश्यक समझे, जांच करेगी और परियोजना के निष्पादन के लिए नियोजित महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों, अधीक्षण इंजीनियरों, कार्यपालक इंजीनियरों और उप-खण्ड अधिकारियों की उन की बाजब सिकारिण करेगी ;

(vi) विभिन्न वर्गों के कार्यों के लिए विनिर्देशों की जांच करेगी और जहां आवश्यक हो वहां उनकी वाजब सिकारिण करेगी ;

(vii) ऐसे सभी उप-प्राकल्पों और संविदाओं की, जिनकी लागत की बाबत संजुरी देना महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों की शक्ति से परे है, जांच करेगी और उनकी बाबत सिफारिश करेगी ;

(viii) महाप्रबंधक/मुख्य इंजीनियरों से संकमों और व्यय, दोनों के लिए, प्राप्त प्रगति रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी और कार्य को शीघ्र करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही की, जहां आवश्यक है, सिफारिश करेगी ।

(5) सन्निर्माण सलाहकार समिति के मुख्यालय समिति नियत करेगी ।

(6) सन्निर्माण सलाहकार समिति अपने कारबार को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया और शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियम बनाएगी ।

(7) सन्निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशें समिति द्वारा सम्बद्ध सरकारों को भेजी जाएंगी और उसकी प्रतियां पुनर्विलोकन समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को जानकारी के लिए भेजी जाएंगी ।

(8) सन्निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशें सामान्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा मान ली जाएंगी । किन्तु असहमति की दशा में, मामला पुनर्विलोकन समिति को भेज दिया जाएगा और पुनर्विलोकन समिति का विनिश्चय अंतिम और सभी सम्बद्ध राज्यों पर बाबदकर होगा ।

सरदार सरोवर बांध और अनुलग्न संकर्म (एकट ए), बिजली घर और उत्पादन मशीनरी (एकक-III) और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रत्येक मामले में अगले उप केन्द्र तक विद्युत् प्रदाय के लिए संचरण लाइनों के सन्निर्माण संबंधी सभी मामलों में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण केवल ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो खण्ड IV के उपखण्ड 16 के अधीन गठित की गई निर्माण सलाहकार समिति पर विनिर्दिष्ट रूप से न्यागत नहीं होते हैं ।

(9) सन्निर्माण सलाहकार समिति, सरदार सरोवर परियोजना के एकक I और III का सन्निर्माण पूरा होने के तीन वर्ष के पश्चात् विवक्षित कर दी जाएगी । एकक I और III का निर्माणोत्तर प्रबंध नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन गुजरात करेगा ।

(10) निर्माण सलाहकार समिति का खर्च मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों राज्य समान रूप से वहन करेंगे ।

#### उपखण्ड 17 :

1977 के सी०एम०पी० 234 और 1977 के सी०एम०पी० 201 में, भारत संघ, अधिकरण के आदेश द्वारा स्थापित किये जाने वाले तंत्र में भाग लेने के लिये, यदि इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाये और अधिकरण का विनिश्चय कार्यान्वित करने की बाबत अथवा सर्वोत्तम प्रयत्न करने के लिये सहमत है ।

#### उपखण्ड 18 :

भारत संघ, अधिकरण के आदेशानुसार स्थापित किये जाने वाले तंत्र में निदेश किये जाने पर, भाग लेने और अधिकरण के विनिश्चय को

क्रियान्वित करने की बाबत सर्वोत्तम उपाय करने के लिये सहमत हो गया है । तदनुसार हम भारत संघ को निवेश देते हैं कि वह अधिकरण के निदेशों को, विशेष रूप से खण्ड 1(2), 4, 12(6), 13, 14 के अधीन दिये गये निदेशों को और साधारणतः सभी अन्य निदेशों को जहां तक उनका संबंध भारत संघ से है, क्रियान्वित करने के लिये अधिकरण के आदेशानुसार गठित तंत्र में भाग ले ।

#### खण्ड XV : कार्यवाहियों के खर्च के संबंध में आदेश :

(i) गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य अधिकरण के समक्ष पेश होने की बाबत अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे । अधिकरण का व्यय उपर्युक्त चारों राज्य समान भाग में वहन और संदत्त करेंगे । इन निदेशों का संबंध अन्तर्राज्य जल-विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) के अधीन निदेशों से है ।

(ii) गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य, उक्त अधिनियम, की धारा 5(3) के अधीन किये गये निदेशों में अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये किये गये खर्च को स्वयं वहन करेंगे । उपर्युक्त निदेशों की बाबत अधिकरण का खर्च गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान बराबर भागों में वहन करेंगे और देंगे ।

#### खण्ड XVI : अंतिम आदेश के कुछ खण्डों के प्रवर्तन की अवधि :

(खंड V में उल्लिखित) खण्ड III और IV के अन्तर्गत सरदार सरोवर बांध के पूर्ण जलाशय स्तर और अधिकतम जल स्तर के संबंध में खण्ड VII में, लागत और लाभ के आबंटन के संबंध में खण्ड VIII में, सरदार सरोवर परियोजना की अपेक्षा के लिये मध्य प्रदेश द्वारा छोड़े जाने वाले जल के संबंध में खण्ड IX में, ऐसे छोड़े गये जल के लिये गुजरात द्वारा मध्यप्रदेश को किये गये जाने वाले भुगतान के संबंध में खण्ड X में, सरदार सरोवर परियोजना के खर्च का सिंचाई और शक्ति के बीच आबंटन संबंधी खण्ड XII में, गुजरात और राजस्थान के बीच सरदार सरोवर परियोजना की लागत के सिंचाई मंडलों के आबंटन संबंधी खण्ड XIII में और तंत्र संबंधी खण्ड XIV में हमारे आदेश, अधिकरण के विनिश्चय के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी भी समय पुनर्विलोकन के अधीन होंगे ।

7 दिसम्बर, 1979

ह०/- बी० रामास्वामी

अध्यक्ष

ह०/- ए० के० सिन्हा

सदस्य

ह०/- एम० आर० ए० अम्बारी

सदस्य

[स० फ़ा० 3/3/79-डब्ल्यू० डी०]

सी० सी० पटेल, सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION****(Department of Irrigation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 1979

**S.O. 792(E).**—Whereas the Central Government had constituted by notification No. S.O. 4054, dated the 6th October, 1969, issued under section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Narmada Water Disputes Tribunal to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river, Narmada and the river valley thereof;

And whereas the said Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government, under sub-section (2) of section 5 of the said Act, a report setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it;

And whereas upon consideration of the said decision, the Central Government and the Governments of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan made references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act and the Tribunal has, on such references, forwarded to the Central Government under that sub-section a further report giving such explanations and guidance as it deemed fit;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby publishes the decision of the said Tribunal as modified by the Tribunal with reference to the explanations and guidance given in its further report.

**DECISION OF THE NARMADA WATER DISPUTES TRIBUNAL AS MODIFIED BY THE EXPLANATIONS AND GUIDANCE GIVEN IN ITS FURTHER REPORT**

**"Final Order And Decision of the Tribunal"**

**Clause 1 : Date of Coming Into Operation Of the Order**

This Order shall come into operation on the date of publication of the Decision of this Tribunal in the Official Gazette under Section 6 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.

**Clause II : Determination Of The Utilisable Quantum Of Narmada Waters At Sardar Sarovar Dam Site**

The Tribunal hereby determines that the utilisable quantum of waters of the Narmada at Sardar Sarovar Dam Site on the basis of 75 per cent dependability should be assessed at 28 Million Acre Feet (34,537.44 M. cu. m.).

**Clause III : Apportionment of The Utilisable Quantum Of Narmada Waters**

(1) The Tribunal hereby orders that out of the utilisable quantum of Narmada waters, (a) Madhya Pradesh is entitled to a share of 18.25 Million Acre Feet (22,511.01 M. cu. m.), (b) Gujarat is entitled to a share of 9 Million Acre Feet (11,101.32 M. cu. m.), (c) Rajasthan is entitled to a share of 0.5 Million Acre Feet (616.74 M. cu. m.) and (d) Maharashtra is entitled to a share of 0.25 Million Acre Feet (308.37 M. cu. m.);

(2) Further, it is clarified that the apportionment relates to actual withdrawals and not consumptive use;

(3) Within its share of water, each party State is free to make such changes in the pattern of water use and in the areas to be benefited within or outside the Narmada basin in its territory as it may consider necessary.

**Clause IV : Order With Regard To Excess Waters And Sharing Of Distress**

(1) The utilisable flow of Narmada in excess of the 28 Million Acre Feet (34,537.44 M. cu. m.) of utilisable flow in

any water year, i.e., from 1st of July to 30th of June of next calendar year is apportioned in the following ratios of allocation i.e., 73 for Madhya Pradesh, 36 for Gujarat, 1 for Maharashtra and 2 for Rajasthan;

(2) In the event of the available utilisable waters for allocation in any water year from 1st of July to 30th June of the next calendar year falling short of 28 Million Acre Feet (34,537.44 M. cu. m.) the shortage should be shared between the various States in the ratio of 73 for Madhya Pradesh, 36 for Gujarat, 1 for Maharashtra and 2 for Rajasthan;

(3) The available utilisable waters in a water year will include the waters carried over from the previous water year as assessed on the 1st of July on the basis of stored waters available on that date;

(4) The available utilisable waters on any date will be inclusive of return flows and exclusive of losses due to evaporation of the various reservoirs;

(5) It may be mentioned that in many years there will be surplus water in the filling period after meeting the storage requirements and withdrawals during the period. This will flow down to sea. Only a portion of it will be utilisable for generating power at Sardar Sarovar river-bed power-house, and the rest will go waste. It is desirable that water, which would go waste without even generating power at the last river-bed power-house, should be allowed to be utilised by the party States to the extent they can.

Gujarat is, therefore, directed that whenever water starts going waste to sea without generating power, or based on the information received from upstream gauging stations, it anticipates that water would so go waste, it shall inform the Narmada Control Authority (hereinafter referred to as the Authority) and designated representatives of all the concerned States. Gujarat shall also inform them when such flows cease. During the period of such flows, the party States, whose reservoirs are spilling and the spill water cannot be stored elsewhere, may utilise such flows from the said reservoirs as they like and such utilisation by the party States will not count towards allotment of supplies to them, but use of such water will not establish any prescriptive rights.

**Clause V : Period of Operation of The Order of Apportionment**

Our Orders with regard to the equitable allocation in Clauses III and IV are made subject to review at any time after a period of 45 years from the date of publication of the Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

**Clause VI : Full Supply Level of The Navagam Canal**

The Tribunal hereby determines that the Full Supply Level of Navagam Canal oftaking from Sardar Sarovar should be fixed at 91.44 m., (+300') at its head regulator with a bed gradient of 1 in 12,000 from head to 290 km. (mile 180), that is, upto the offtake of Saurashtra branch. From that point to Rajasthan border the bed gradient should be 1 in 10,000. These bed gradients may be changed by Gujarat and Rajasthan by mutual agreement. Gujarat and Rajasthan shall be at liberty to decide the canal capacity required by each in the light of water which would be expected to be available within their share.

**Clause VII : Full Reservoir Level And Maximum Water Level Of The Sardar Sarovar Dam**

The Tribunal hereby determines that the height of the Sardar Sarovar Dam should be fixed for Full Reservoir Level +138.68 m., (+455') and Maximum Water Level at +140.21 m., (+460'). Gujarat shall take up and complete the construction of the dam accordingly.

**Clause VIII : Sharing Of Costs And Benefits.**

(1) (i) The Tribunal hereby determines that out of the net power produced at Navagam at canal head and river

bed power houses on any day the share of Madhya Pradesh will be 57 per cent; Maharashtra's share will be 27 per cent and Gujarat's share will be 16 per cent.

(ii) The party States shall make available in annual instalments their share of funds required according to approved construction programme and take all the necessary steps to complete the Sardar Sarovar Dam within ten years of the date of publication of the Final Order and Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

(2) The Tribunal makes the following further Orders:—

- (i) The power generated in the River Bed and Canal Power Houses at Navagam will be integrated in a common switchyard.
  - (ii) Madhya Pradesh and Maharashtra will be entitled to get 57 per cent and 27 per cent respectively of the power available at bus bar in the switchyard after allowing for station auxiliaries.
  - (iii) The above entitlement applies both to availability of machine capacity for peak loads and to the total energy produced in any day.
  - (iv) The entitlement of power and energy for any day can be utilised fully or partly by the concerned States or sold to another participating State under mutual agreement. It cannot, however, be carried forward except under a separate agreement or working arrangement entered into among the affected parties.
  - (v) Gujarat will construct and maintain the transmission lines needed to supply the allotted quantum of power to Madhya Pradesh and Maharashtra upto Gujarat State border, along an alignment as agreed to between the parties and if there is no agreement, along such alignment as may be decided by the Narmada Control Authority. The transmission lines beyond Gujarat State border shall be constructed and maintained by Madhya Pradesh and Maharashtra in their respective States.
  - (vi) The power houses and appurtenant works including the machinery and all installations as well as the transmission lines in Gujarat State will be constructed, maintained and operated by Gujarat State or an authority nominated by the State.
  - (vii) The authority in control of the Power Houses shall follow the directions of the Narmada Control Authority in so far as use of water is concerned.
  - (viii) The scheme of operation of the Power Houses including the power required and the load to be catered for the different party States during different parts of the day shall be settled between the States at least one week before the commencement of every month and shall not be altered during the month except under agreement among the States or under emergencies.
- If and when Sardar Sarovar Power Complex gets linked with the Regional or National Power Grid, the operation of the Sardar Sarovar Power Complex will be governed by such altered system conditions. But in that event the Narmada Control Authority should arrange to take such steps as are necessary to enable the three States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra to get their entitlement of power and energy from the Sardar Sarovar Power Complex according to these orders.
- (ix) The capital cost of the power portion of Navagam Complex shall comprise the following :—
    - (a) Full cost of Unit III electrical works and control works pertaining thereto, upto and including the switchyard.
    - (b) Full cost of transmission lines in Gujarat State constructed for supplying power to Madhya Pradesh and Maharashtra.
    - (c) 56.1 per cent of the net cost of common facilities such as Dam and Appurtenant Works i.e. Unit I of Sardar Sarovar Project, after allowing for credits, if any ;
    - (d) 56.1 per cent of the credit given to Madhya Pradesh for the downstream benefits derived from Narmadasagar Dam.
    - (x) Madhya Pradesh and Maharashtra shall respectively pay to Gujarat 57 per cent and 27 per cent of the capital cost of the power portion of the Sardar Sarovar headworks worked out vide (ix) above. This amount shall be paid in annual instalments until the capital works are completed. Each instalment will be worked out on the basis of the budgeted figures of the concerned works at the commencement of each financial year and shall be set off and adjusted against actual figures at the end of the financial year.
    - (xi) In addition to the payments vide (x) above, Madhya Pradesh and Maharashtra shall also pay to Gujarat 57 per cent and 27 per cent respectively of the operation and maintenance costs of the Sardar Sarovar Power Complex each year. These payments are also to be based on budgeted figures at the commencement of each financial year and adjusted against actual cost at the end of the year.
    - (xii) Notwithstanding the directions contained hereinabove, the party States may, by mutual agreement, alter, amend, or modify any of the directions in respect of sharing of power and payment for it.

#### Clause IX : Regulated Releases to be made by Madhya Pradesh for the requirement of Sardar Sarovar Project

With regard to the quantum and pattern of regulated releases, the Tribunal makes the following Order :—

It has been agreed by the party States and decided by the Tribunal in its Order dated 8th October, 1974, that the utilisable quantity of water of 75 per cent dependability in the Narmada at Sardar Sarovar dam site should be assessed at 28 MAF (34, 537.44 M.cu.m.). The actual inflow of 75 per cent dependability, however, is only 33, 316.29 M. cu.m. (27.01 MAF) and this is brought up to utilisable quantity of 28 MAF (34, 537.44 M.cu.m.) by means of carryover in various reservoirs allowing for evaporation losses and regeneration. Out of 28 MAF (34, 537.44 M. cu.m.), 11, 101.32 M.cu.m. (9 MAF) has to be provided for Gujarat and 0.5 MAF (616.74 M.cu.m.) for Rajasthan at Sardar Sarovar. The requirements at Sardar Sarovar have to be met by releases by Madhya Pradesh and by inflows from the intermediate catchment, surplus to the requirements of Madhya Pradesh below Narmadasagar and Maharashtra. The releases from Maheshwar work out to 10,015.86 M.cu. m. (8.12 MAF). Making uniform monthly releases the amount of water to be released by Madhya Pradesh per month would be 834.65 M.cu.m. (0.677 MAF). The actual inflow in the river system, however, would vary from year to year and, therefore, the releases by Madhya Pradesh would also vary.

The inflow during the filling period, July to October, cannot be predicted at the beginning of the season. It is only in October that it would be fully known whether the particular year is a normal year or the extent to which it is a surplus or deficit year. Normally the releases by Madhya Pradesh during the filling period, therefore, would have to be more or less on the basis of the year yielding 28 MAF (34,537.44 M.cu.m.) utilisable quantity. The month of July and early part of August are crucial for Kharif sowing. It is important that during this period regulatory arrangements should ensure that due share of water is made available to all parties.

Having regard to the facts mentioned in the preceding two paragraphs, we order that detailed rules of regulation and water accounting shall be framed by Narmada Control Authority in accordance with the guidelines given below. These guidelines may, however, be altered, amended or modified by agreement between the States concerned.



- (i) The 28 MAF (34,537.44 M.cu.m.) utilisable supplies of 75 per cent dependability in a water year (1st July to 30th June next year) shall be shared by the party States as under :—

Madhy Pradesh	—	18.25 MAF (22,511.01 M.cu.m.)
Gujarat	—	9.00 MAF (11,101.32 M.cu.m.)
Rajasthan	—	0.50 MAF ( 616.74 M.cu.m.)
Maharashtra	—	0.25 MAF ( 303.37 M.cu.m.)
<hr/>		
28.00 MAF (34,537.44 M.cu.m.)		

- (ii) Surplus or deficit utilisable supplies in a water year shall be shared to the extent feasible by the party States in the same proportion as their allotted shares in (i) above. The surplus water shall first be utilised for filling up the reservoirs to capacity and surplus water shall be utilised for irrigation and other purposes only after that has been ensured.
- (iii) The water available in the live storages of the various reservoirs on 30th June shall be reckoned as an inflow to be shared in the next water year.
- (iv) The releases necessary to ensure Gujarat and Rajasthan's share of water in a water year shall be let down by Madhya Pradesh at a reasonably uniform rate, permitting only such variation as the Authority may direct or approve and keeping in view the directions for regulated releases.
- (v) The Authority shall ensure by so directing the releases by Madhya Pradesh that there is at all times sufficient utilisable water in Sardar Sarovar to meet the requirements of the next ten days, subject to water being available in the storages in Madhya Pradesh after taking into account the proportionate requirements of Madhya Pradesh. For this purpose, Gujarat and Rajasthan would intimate their requirements of the 10 daily period well in advance.
- (vi) Utilisation in a water year by each party State shall be figured out on the basis of actual daily discharge at canal head on every major and medium project. For minor works, it shall be on the basis of area irrigated under different crops, the delta for each crop being approved by the Authority. For pumping schemes, drawing directly from the river, its tributaries or reservoirs, whether for irrigation, domestic or industrial use, water drawn shall be reckoned on the basis of the rated capacity of pumps and the number of hours they run. For a cross check, the seasonwise and cropwise area irrigated by each pumping scheme shall also be recorded, and if the figures of water drawn as worked out by the two aforesaid methods differ, the decision of the Authority as regards water, drawn shall be final.
- (vii) Withdrawals from Sardar Sarovar for Navagam Canal for Gujarat and Rajasthan shall be measured at the head of Navagam Canal. The supply to Rajasthan shall be measured at Gujarat-Rajasthan border. The loss in the canal in carrying the supply for Rajasthan shall be determined by the Authority after the canal has been constructed and shall reckon against the share of Rajasthan.

Water let down into the river from Sardar Sarovar through power house turbines shall be measured on the basis of power generated by it and that escaped through the spillway measurement at the spillway.

Gujarat may let down water from Sardar Sarovar for its downstream use by making specific indent for it and such release shall reckon against its share. Such releases for downstream use shall be made through the turbines and the power so generated shared between Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat in the prescribed ratio. Water let down into the river from Sardar Sarovar except at the

specific indent of Gujarat shall not reckon against the share of Gujarat.

The water drawn from Sardar Sarovar for use in Madhya Pradesh and Maharashtra, as the case may be, shall reckon against the share of water of that State.

- (viii) For major and medium projects, water account shall be kept by 10 daily period. The last 10 daily period of a month may have 11 days, 10 days or less, depending upon the number of days in the month. For minor schemes water accounts shall be kept by crop season, kharif (July to October) rabi (November to March) and hot weather (April to June). For pumping schemes and domestic and industrial uses it shall be monthly.
- (ix) The water use by minor and pumping schemes in any ten daily period may provisionally be taken to be the same as in the corresponding period in the previous year on the basis of average use during the crop period. For final water account, however, it will be determined as in (vi) above.
- (x) Each State shall furnish to the Authority and make available to any party State desiring the same, such data and information as the Authority may require and ask for.
- (xi) The Authority shall arrange the review of the ten day releases made by Madhya Pradesh at least once a month and oftener as considered necessary for directing any change in the releases. It may designate a person for doing so.
- (xii) The Authority shall direct final adjustment to be made in the following water year of the use in excess of the authorised use, if any, by any State or States during the preceding water year by curtailing the share(s) of the State or States concerned which have used water in excess and make over the same to the State or States which have received short supplies. Water supplied to Rajasthan on any day in excess of 10 per cent over and above its indent shall reckon against use by Gujarat.
- (xiii) The Authority shall furnish the annual water account for the water year to the Governments of the party States by the end of August of the next water year. Each State may make any observation on the account and/or point out corrections in it, if any, within one month of its receipt. After making the necessary modifications, the Authority shall furnish to each party State the final annual water account for the water year by 31st October. The Authority shall cause the annual water account to be published each year.

Clause X : Payment to be made by Gujarat to Madhya Pradesh for such regulated releases.

(1) Madhya Pradesh shall take up and complete the construction of Narmadasagar dam with FRL 262.13 m (860 ft.) (concurrently with or earlier than the construction of Sardar Sarovar dam.

(2) The Tribunal further orders that Gujarat should credit to Madhya Pradesh each year 17.63 per cent of the expenditure on account of Narmadasagar dam in the financial year commencing from the year of taking up of the construction of Narmadasagar dam. This will be initially credited on the basis of budget allotment to be adjusted at the end of the year on actual expenditure. The post construction expenditure on maintenance is not to be considered as cost of construction.

Clause XI : Directions Regarding Submergence, Land Acquisition and Rehabilitation of Displaced Persons.

Sub-clause 1 : Definitions.

1(1) : "Land".—The expression "land" shall have the same meaning as defined in the Land Acquisition Act, 1894. (hereinafter referred to as the Act) which states "the expression 'land' includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth."

1(2) : "Oustee".—An 'oustee' shall mean any person who since at least one year prior to the date of publication of

the notification under Section 4 of the Act, has been ordinarily residing or cultivating land or carrying on any trade, occupation, or calling or working for gain in the area likely to be submerged permanently or temporarily.

1(3) : "Family".—(i) A family shall include husband, wife and minor children and other persons dependent on the head of the family, e.g., widowed mother.

(ii) Every major son will be treated as a separate family.

Sub-clause II.—Lands which are to be compulsorily acquired.

II(1) : Madhya Pradesh and Maharashtra shall acquire for Sardar Sarovar Project under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, all lands of private ownership situated below the FRL + 138.68 m (455') of Sardar Sarovar and all interests therein not belonging to the respective States. If on the basis aforesaid, 75 per cent or more land of a contiguous holding of any person is required to be compulsorily acquired, such person shall have the option to compel compulsory acquisition of the entire contiguous holding.

II(2) : Madhya Pradesh and Maharashtra shall also acquire for Sardar Sarovar Project under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, all buildings with their appurtenant land situated between FRL + 138.68 m (455') and MWL + 141.21 m (460') as also those affected by the backwater effect resulting from MWL + 141.21 m (460').

II(3) : The backwater level at the highest flood level in Sardar Sarovar shall be worked out by the Central Water Commission in consultation with Madhya Pradesh and Gujarat.

Sub-clause III.—Liability of Gujarat to pay compensation for Land Acquisition and Rehabilitation etc.

III(1) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra all costs including compensation charges and expenses incurred by them for or in respect of the compulsory acquisition of lands required to be acquired as aforesaid.

III(2) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union of India compensation for the respective Government lands and structures on principles similar to those underlying the Land Acquisition Act, 1894. Where any dispute or difference arises between Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and the Union of India with respect to the compensation payable as aforesaid, any of the three States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra or the Union of India may refer the matter in dispute to arbitration. The State of Gujarat on the one hand and the States of Madhya Pradesh, Maharashtra or the Union of India (as the case may be) on the other hand shall respectively nominate one Arbitrator each. In the event of disagreement between the Arbitrators, such dispute or difference shall be referred to an Umpire who shall be a person appointed in that behalf by the Chief Justice of India from among persons who are, or have been Judges of the Supreme Court. The decision of the Arbitrators, or, as the case may be, of the Umpire shall be final and binding on the parties and shall be given effect to by them.

III(3) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra land revenue in accordance with the respective Land Revenue Codes of Madhya Pradesh and Maharashtra in respect of all lands in their respective territories acquired for Gujarat or conveyed to it.

III(4) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra all costs, charges and expenses incurred by Madhya Pradesh and Maharashtra for the purpose of removal and reinstallation of any ancient or historical monuments, archaeological remains, religious place of worship or idols likely to be affected by submergence under Sardar Sarovar and that in the event of such payment being made, no separate compensation as hereinbefore provided shall be required to be paid in respect of the same having been affected by the submergence.

III(5) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra all costs, charges and expenses required to be incurred by them for rehabilitation of oustees and oustee families in their respective territories in accordance with the directions hereinafter contained.

III(6) : Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra costs on account of establishment charges for land

acquisition and rehabilitation and other departmental staff which Madhya Pradesh and Maharashtra may consider necessary for the purpose of such acquisition and rehabilitation.

Sub-clause IV.—Provision for Rehabilitation.

IV(1) : According to the present estimates the number of oustee families would be 6147 spread over 158 villages in Madhya Pradesh, 456 families spread over 27 villages in Maharashtra. Gujarat shall establish rehabilitation villages in Gujarat in the irrigation command of the Sardar Sarovar Project on the norms hereinafter mentioned for rehabilitation of the families who are willing to migrate to Gujarat. For oustee families who are unwilling to migrate to Gujarat, Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra the cost, charges and expenses for establishment of such villages in their respective territories on the norms as hereinafter provided.

IV(2)(i) : According to the present estimates the number of oustee families below RL 106.68 metres (RL 350') would be 30 spread over 20 villages in Madhya Pradesh and 250 families spread over 20 villages in Maharashtra. Within six months of the publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra shall determine by mutual consultation the location of one or two rehabilitation villages in Gujarat to rehabilitate oustees from areas below RL 106.68 metres (RL + 350'). Gujarat shall acquire necessary lands for the rehabilitation villages and make available the same within two years of the decision of the Tribunal. Within six months of the decision of the location of the rehabilitation villages in Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra shall intimate to Gujarat the number of oustee families from areas below RL 106.68 metres (RL 350') willing to migrate to Gujarat. For the remaining oustee families, Madhya Pradesh and Maharashtra shall arrange to acquire lands for rehabilitation within the respective States.

IV(2)(ii) : Madhya Pradesh and Maharashtra shall set up adequate establishments for land acquisition and rehabilitation of oustee families. Gujarat shall deposit within three months of the decision of the Tribunal Rupees ten lakhs each with Madhya Pradesh and Maharashtra in advance towards cost of establishment and rehabilitation in these States to be adjusted after actual costs are determined. Madhya Pradesh and Maharashtra shall start land acquisition proceedings for areas below RL 106.68 metres (RL + 350'), within six months of the decision of the Tribunal and convey the lands to Gujarat for project purposes within three years of the decision of the Tribunal. Within 18 months of the decision of the Tribunal, Gujarat shall make an advance payment of Rs. 70 lakhs to Madhya Pradesh and Rs. 100 lakhs to Maharashtra towards the compensation of land, to be adjusted after actual costs are determined.

IV(2)(iii) : Regarding the oustee families from areas above RL 106.68 metres (RL + 350'), Gujarat shall intimate to Madhya Pradesh and Maharashtra within six months of publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette the number and general location of rehabilitation villages proposed to be established by Gujarat in accordance with the decision of the Tribunal. Within one year of the receipt of proposal of Gujarat, both Madhya Pradesh and Maharashtra shall intimate to Gujarat the number of oustee families willing to migrate to Gujarat. The three States by mutual consultation shall determine within two years of the decision of the Tribunal, the number and general location of rehabilitation villages required to be established by Gujarat in its own territory. Madhya Pradesh and Maharashtra shall intimate to Gujarat the number of such villages to be established in Madhya Pradesh and Maharashtra and for which Gujarat would be required to make payments to Madhya Pradesh and Maharashtra respectively.

IV(2)(iv) : Gujarat shall acquire and make available a year in advance of the submergence before each successive stage, irrigable lands and house sites for rehabilitation of the oustee families from Madhya Pradesh and Maharashtra who are willing to migrate to Gujarat. Gujarat shall in the first instance offer to rehabilitate the oustees in its own territory.



IV(3) : Gujarat shall also provide the following grants and amenities to the oustees :—

(a) Resettlement Grants (Rehabilitation Grant)—Gujarat shall pay per family a sum of Rs. 750 inclusive of transportation charges as resettlement grant.

(b) Grant-in-aid.

In addition, Gujarat shall pay per family grant-in-aid in the following scale :—

Where total compensation is received	Grant-in-aid
Above Rs. 2000/-.	Nil.
Between Rs. 2000/- and Rs. 500/-.	Rs. 500/- less an amount equal to one-third of the compensation in excess of Rs. 500/-.
Less than Rs. 500/-.	Rs. 500/-.

(c) Civic amenities :

1. One primary school (3 rooms) for 100 families.
2. One Panchayat Ghar for every 500 families.
3. One Dispensary for every 500 families.
4. One seed store for every 500 families.
5. One children's park for every 500 families.
6. One village pond for every 500 families.
7. Drinking water well with trough for every 50 families.
8. Each colony should be linked to main road by roads of appropriate standard.
9. One platform for every 50 families.
10. Every oustee family shall be entitled to and allotted a house site i.e., a plot of land measuring 18.29 × 27.43m. (60' × 90') free of cost. In addition, a provision of 30 per cent additional area for roads, Government buildings, open space etc. shall be made by Gujarat under civic amenities.

11. The State of Gujarat shall make the following provision for rehabilitation in Madhya Pradesh and Maharashtra :

	Rs.
(a) Resettlement . . . . .	750 per family.
(b) Grant-in-aid . . . . .	500 per family.
(c) Acquisition of land for resettlement of families affected @ 0.40 hectares (one acre) for 6 families . . . . .	1500 per acre.
(d) Civic amenities:	
1. One primary school @ 100 families . . . . .	30000 each.
2. One Community Hall-cum-Panchayat Bhavan @ 500 families . . . . .	20000 each.
3. One Dispensary @ 500 families . . . . .	25000 each.
4. One seed store @ 500 families . . . . .	10000 each.
5. One Children's Park @ 500 families . . . . .	6000 each.

6. One Well with trough @ 50 families . . . . . 10000 each.
7. One pond @ 500 families . . . . . 20000 each.
8. One tree platform @ 50 families. . . . . 1500 each.
9. One religious place of worship @ 100 families . . . . . 1000 each.
10. Construction of approach roads and link roads for Abadies 3 km per every new Abadi . . . . . 30000 per km.
11. Electrical distribution lines and street lights 2 km per 100 families . . . . . 11000 per km.
12. Social amenities for each municipal town going under submergence, viz., water supply and sanitary arrangements layout, levelling of site etc. . . . . 5,00,000 each town

IV (4)(i) : Gujarat is directed to provide for rehabilitation and civic amenities as per directions contained hereinabove in Sub-clause IV(3) in its estimate for B-Land compensation and rehabilitation.

IV(4)(ii) : Notwithstanding the provisions hereinbefore contained, Gujarat shall not be liable to pay any compensation for the loss of public properties, facilities or amenities such as drinking water wells, primary school buildings, internal roads, village sites, approach roads, dispensaries, Panchayat buildings, rural electrification, highway bridges, telegraph lines, power lines, etc., if corresponding alternative properties, facilities or amenities are to be provided at the cost of the Sardar Sarovar Project. The party owning the facility shall have the option to accept compensation for utilities as existing or ask for their replacement or relocation at the cost of Gujarat.

IV(5) : It is made clear that the monetary values in Clause IV(3)(c) are liable to be changed at the time of actual rehabilitation. Where any dispute or difference arises as regards the changed valuation, the matter shall be determined by Arbitration in the manner provided in Clause III(2) above and Gujarat's liability shall stand altered accordingly.

IV(6)(i) : In the event of Gujarat being unable to resettle the oustees or the oustees being unwilling to occupy the area offered by Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra shall make such provisions for rehabilitation, civic amenities etc. on the lines mentioned in Clauses IV(1) to (4) above. Gujarat shall, in that event, be liable to pay all such expenses, costs etc., arising out of or in connection with rehabilitation and provision of civic amenities for the oustees including the cost of all acquisition proceedings and payment of compensation etc., as per the Land Acquisition Act, for the land allotted to oustees for cultivation and habitation.

IV(6)(ii) : In no event shall any areas in Madhya Pradesh and Maharashtra be submerged under the Sardar Sarovar unless all payment of compensation, expenses and costs as aforesaid is made for acquisition of land and properties and arrangements are made for the rehabilitation of the oustees the reform in accordance with these directions and intimated to the oustees.

IV(7) : Allotment of Agricultural Lands.—Every displaced family from whom more than 25 per cent of its land holding is acquired shall be entitled to and be allotted irrigable land to the extent of land acquired from it subject to the prescribed ceiling in the State concerned and a minimum of 2 hectares (5 acres) per family, the irrigation facilities being provided by the State in whose territory the allotted land is situated. This land shall be transferred to the oustee family if it agrees to take it. The price charged for it

would be as mutually agreed between Gujarat and the concerned State. Of the price to be paid for the land a sum equal to 50 per cent of the compensation payable to the oustee family for the land acquired from it will be set off as an initial instalment of payment. The balance cost of the allotted land shall be recovered from the allottee in 20 yearly instalments free of interest. Where land is allotted in Madhya Pradesh or Maharashtra, Gujarat having paid for it vide Clause IV(6)(i) supra, all recoveries for the allotted land shall be credited to Gujarat.

IV(8): Any dispute between the State in respect of Clauses IV(1) to (7) of these directions shall be referred to and determined by arbitration in the manner provided in Clause III(2) of these directions.

Sub-clause V. Programme for Payment to be made by Gujarat to Madhya Pradesh and Maharashtra

V(1): As soon as practicable after the publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette, Gujarat shall prepare and furnish to the other party States, a fresh estimate of sub-head B-Land for the Sardar Sarovar Project as permitted by the Tribunal including in particular, costs of acquisition of lands in Madhya Pradesh and Maharashtra and of rehabilitation of oustee families in Madhya Pradesh and Maharashtra.

V(x)(i): As soon as practicable after the publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette and in any case before expiry of three months thereafter, both Madhya Pradesh and Maharashtra shall furnish to Gujarat three sets of Majmuli/Taluka maps of all talukas in their respective territories likely to be submerged wholly or partly under Sardar Sarovar. These maps shall indicate village boundaries. Within three months after the receipt of the Majmuli/Taluka maps Gujarat shall mark thereon the boundary of the area situated below the FRL as also that between FRL and MWL including the area affected by back water resulting from MWL and shall return one respective set so marked to Madhya Pradesh and Maharashtra.

V(2)(ii): As soon as practicable after the receipt of one set of the Majmuli/Taluka maps marked as aforesaid and in any case within six months thereof, the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra shall publish notifications under Sub-section (1) of Section 4 of the Act notifying that the lands in their respective territories situated below the FRL and buildings with their appurtenant lands between FRL and MWL, as also those affected by the back water effect resulting from MWL (to be specified in the notification) are likely to be needed for the Sardar Sarovar Project.

V(2)(iii): As soon as practicable after publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette as hereinbefore referred to and in any case within one year thereof, Gujarat shall intimate to Madhya Pradesh and Maharashtra yearwise programme of construction of the dam.

V(2)(iv): Objections, if any, received against the proposed acquisition of lands as notified under Section 4 of the Act shall be heard and disposed of and any reports to the State Governments as contemplated by Sub-section (2) of Section 5A of the Act shall be made with utmost expedition. The Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra shall issue requisite notifications under Section 6 of the Act with utmost expedition and in any case before the expiry of three years from the dates of publication of the respective notifications under Sub-section (1) of Section 4 of the Act.

V(2)(v): As soon as practicable, after receipt of the yearwise programme of construction of the Sardar Sarovar Dam from Gujarat both Madhya Pradesh and Maharashtra in consultation with Gujarat shall finalise their respective yearwise programme of completing the proceedings for compulsory acquisition of lands in their respective territories upto the stages of making awards under Section 11 of the Act and of taking possession of the lands under Section 16 of the Act.

V(3)(i): Gujarat is required to pay to Madhya Pradesh and Maharashtra compensation for compulsory acquisition of lands, market value of Government lands to be conveyed to Gujarat and expenditure to be incurred in connection with

the rehabilitation of oustee families to be rehabilitated in Madhya Pradesh and Maharashtra as hereinbefore provided. Madhya Pradesh and Maharashtra shall on or before 30th September of each year intimate to Gujarat the amounts required to be paid by Gujarat to Madhya Pradesh and Maharashtra respectively having regard to (a) the extent of lands in Madhya Pradesh and Maharashtra in respect of which awards are likely to be made under Section 11 of the Act (b) the extent of Government lands likely to be conveyed by Madhya Pradesh and Maharashtra to Gujarat during the next financial year and (c) the expenditure likely to be incurred by Madhya Pradesh and Maharashtra in connection with rehabilitation of oustee families in Madhya Pradesh and Maharashtra during the next financial year. In arriving at these estimates for the next financial year, Madhya Pradesh and Maharashtra shall also take into account the differences, if any, between the payments made by Gujarat in pursuance of this clause for the current financial year and the amount actually payable during the said financial year.

V(3)(ii): On the basis of these estimates, Gujarat shall on or before the 31st May of the following financial year make payments to Madhya Pradesh and Maharashtra of the amounts estimated as provided in Clause V(3)(i) above.

V(3)(iii): Gujarat shall at each successive stage of submergence intimate to Madhya Pradesh and Maharashtra the area coming under submergence at least 18 months in advance. The inhabitants of the area coming under the respective stages of submergence will be entitled to occupy or use their properties without being required to pay anything for such occupation and use till a date to be notified by the State concerned which date shall not be less than six months before submergence. They must vacate the area by the notified date.

V(4)(i): On payment of the amounts to be paid each year by Gujarat as compensation for compulsory acquisition of lands as aforesaid, Madhya Pradesh and Maharashtra shall, as expeditiously as possible, complete the acquisition and transfer such lands to Gujarat so as to vest the lands in Gujarat to be used only for the purpose of submergence and subject to Clauses V(5) to (8) of these directions.

V(4)(ii): On payment of the market value of Government lands by Gujarat as hereinbefore provided Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union of India shall convey such lands to Gujarat so as to vest in Gujarat to be used only for the purpose of submergence and subject to Clauses V(5) to (8) of these directions.

V(5): Gujarat shall pay to Madhya Pradesh and Maharashtra in accordance with the respective Land Revenue Codes, the amount of land revenue payable every year for the lands in their respective territories acquired for Gujarat or conveyed to it, at the rates prevailing in Madhya Pradesh and Maharashtra respectively from time to time.

V(6): Madhya Pradesh and Maharashtra, as the case may be, shall remit each year to Gujarat any revenue which they may derive from the cultivation of lands which get periodically exposed in Sardar Sarovar, after deducting collection charges for the same.

V(7): Notwithstanding vesting in Gujarat of the lands coming under submergence, Madhya Pradesh and Maharashtra shall continue to enjoy all rights of sovereignty intact over the submerged area in the respective States.

V(8): Madhya Pradesh and Maharashtra respectively shall be exclusively entitled to all rights of fishing, boating and water transportation over the part of lake over the submerged land within Madhya Pradesh and Maharashtra respectively, provided, however, that such right is not exercised to the prejudice of any utilities of the Sardar Sarovar Project or cause hindrance in the legitimate performance of their duties by the project personnel.

V(9): All residual rights not specifically transferred to Gujarat in respect of the lands coming under submergence shall continue to vest in the Government in whose territory they are situated.



V(10) : In the event of the said lands not being used for the purpose of submergence for which it is acquired, the State of Gujarat shall retransfer such land to Madhya Pradesh or Maharashtra as the case may be, subject to the condition that Madhya Pradesh and Maharashtra refund to Gujarat the amount of compensation received from Gujarat in respect of such land.

V(11) : In the event of any land acquired for rehabilitation of oustee families is not used for the purpose, it shall be returned to the original owner on payment, where feasible or otherwise disposed of and due credit given to Gujarat.

V(12) : All costs incurred by Gujarat on acquisition of land and rehabilitation of oustees in respect of Sardar Sarovar shall be charged to Sardar Sarovar Project estimate. Unit I—Dam and Appurtenant Works.

#### Sub-clause VI :

Nothing contained in Clause XI shall prevent the alteration, amendment and modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between all the party States.

Clause XII : Allocation of Cost of Sardar Sarovar Project between Irrigation and Power.

We determine that the cost of Unit I—Dam and Appurtenant Works—should be apportioned between Irrigation and Power as follows :—

Irrigation	-- 43.9 per cent
Power	-- 56.1 per cent

Clause XIII : Allocation of Irrigation Component of Cost Sardar Sarovar Project and between Gujarat and Rajasthan.

(a)(i) The irrigation component of the cost of Unit I of Sardar Sarovar Project (Dam and Appurtenant Works) should be shared by Gujarat and Rajasthan in the ratio of 18 : 1.

(a)(ii) Madhya Pradesh and Maharashtra shall contribute a pro rata share to the irrigation component of the cost of Sardar Sarovar Dam as also towards its operation and annual maintenance, for water drawn from Sardar Sarovar for use in their territory. The pro rata share shall be in proportion of the quantity of water so drawn to 9.5 MAF. The amount so contributed shall be credited to Gujarat and Rajasthan in the ratio of 18 : 1.

(b) The cost of Navagam Canal with its design approved by Narmada Control Authority shall be shared by the two States as under :—

- (i) The cost differential in respect of land, earth work and lining for the gradients proposed by Gujarat and that now prescribed, to be borne by Rajasthan in full.
- (ii) The actual cost of the canal less (i) above to be shared on cusec mile basis.

The actual cost should be shared by Gujarat and Rajasthan on cusec-mile basis in the first instance and on completion of the work the share cost shall be adjusted as indicated above. Rajasthan shall credit its share cost each year initially on the basis of budget allotment. This should then be adjusted at the end of the year to actual expenditure. The post-construction expenditure on maintenance is not to be considered as cost of construction.

Should any difference arise between Rajasthan and Gujarat on figures of cost in respect of Navagam Main Canal for purposes of sharing the cost, the matter shall be referred to the Narmada Control Authority and on such a reference its decision shall be final and binding.

Clause XIV : Setting up of Machinery for Implementing The Decision of the Tribunal

We make the following orders with regard to setting up of machinery for implementing the decision of the Tribunal :

#### Sub-Clause 1 : Constitution of the Authority.

1(1) : An inter-State administrative authority to be called Narmada Control Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') shall be established for the purpose of securing compliance with and implementation of the decision and directions of the Narmada Water Disputes Tribunal (herein referred as the 'Orders').

1(2) : The Authority shall consist of seven high-ranking Engineer Members, of whom one each shall be of the rank of Engineer-in-Chief, Chief Engineer, or Additional Chief Engineer of the Irrigation Department, Power Department or the State Electricity Board appointed by the Government of each of the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan and three other eminent Engineers of a rank not less than that of a Chief Engineer to be appointed by the Central Government in consultation with the party States. One of the three Independent Members shall be nominated by the Central Government, as the Chairman of the Authority with a deliberative vote at meetings where decisions are taken on any matter affecting the interest of more than one State and he will be in charge of the administrative work of the Authority. The Central or State Government, as the case may be, shall have the power to remove or suspend from the Authority any Member who, in its opinion, is not suitable to continue as Member.

1(3) : Each Independent Member shall be a full-time Members and be appointed for a term not exceeding five years. The Members appointed by the State Governments shall be part-time Members. The appointing authority for Independent Member or that for part-time Member, as the case may be, shall determine the terms and conditions of appointment in each case. As far as practicable, the first appointment of the seven members of the Authority shall be made within three months from the date of publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette.

#### 1(4) : Vacancies of Members.

On any vacancy occurring in the offices of the three independent Members, the Central Government shall appoint a person to such vacant office, and on any vacancy occurring in the office of the four Members other than the independent Members, the State Government by whom the Member whose office falls vacant was appointed shall appoint a person to the vacant office.

In case of illness or absence for any cause whatever of a Member, the Central Government or State Government by whom he was appointed (as the case may be) may appoint a person as an acting Member during such illness or absence and such acting Member shall, while so acting, have all the powers and perform all the duties and be entitled to the indemnities of the Member (vide Sub-clause 5) in whose stead he so acts, save and except that the next senior independent Member appointed by the Central Government and not the acting Member shall act as Chairman at business meeting of the Authority or as the Chairman of the Authority in the event of illness or absence of the Chairman of the Authority.

#### Sub-clause 2 : Secretary of the Authority :

The Authority shall employ a Secretary, who shall be an Engineer. He shall not be a Member of the Authority.

#### Sub-clause 3 : Quorum and Voting :

Five Members shall be a quorum and the concurrence of the majority shall be necessary for the transaction of the business of the Authority except such business as the Authority may from time to time prescribe as routine. The Authority shall not prescribe as routine any business in which the interests of any two of the States are likely to be in conflict. For the transaction of routine business three Members shall be a quorum and in the absence of the Chairman of the Authority, the Chairman elected at the meeting shall have a deliberative vote and in the event of an equality of votes a casting vote also.

Subject as aforesaid the Members shall have equal powers.

#### Sub-clause 4 : Disposal of Business by the Authority.

4(1) : Subject to the provisions of Sub-clause 4(2), below, the Authority may dispose of any matter before it either by

circulation or by holding a meeting. However, it will be open to any Member of the Authority to require that a matter shall not be disposed of by circulation but at a meeting.

4(2) : On the following matters the Authority shall record its decision by a Resolution at a meeting in which the Chairman and all the Members from the party States are present :

- (i) Framing of Rules of Business;
- (ii) Delegation of functions to a Member or Secretary or any official of the Authority;
- (iii) Categorising any part of the business of the Authority as of a formal or routine nature ;
- (iv) Any other matter which any of the four party States require that it shall be decided at a meeting where all the members from the party States are present.

However, if any particular item under this Sub-clause cannot be disposed of at two successive meetings owing to the absence of one or more Members from the party States, it shall be disposed of under Sub-clause 3 of Clause XIV.

4(3) : Subject to the foregoing provisions, the Authority shall frame its own Rules for the conduct of its business.

4(4) : The Authority shall cause proper minutes or records of all its proceedings to be kept as a permanent record.

Sub-clause 5 : Indemnity of Members :

No Member, officer or employee of the Authority shall be liable for loss, injury or damages resulting from (a) action taken by such Member, officer or employee in good faith and without malice under the apparent authority of the Orders, even though such action is later determined to be unauthorised, or (b) the negligent or wrongful act of omission of any other person, employed by the Authority and serving under such Member, officer or employee unless such Member, officer or employee failed to exercise due care in the appointment of such other person or the supervision of his work.

Sub-clause 6 : Officers and Servants of the Authority.

The Authority may from time to time appoint or employ such and so many officers and servants as it thinks fit and remove or dismiss them, under the rules and regulations applicable to the appointment, removal and dismissal of the Central Government officers and servants. All such officers and servants shall as such be subject to the sole control of the Authority. The scales of pay and other service conditions shall be as applicable to Central Government employees.

Persons employed in the services of the four States may be appointed or employed by the Authority in such proportions as the Authority may deem fit. The Authority shall arrange with the State Governments to spare the services of the persons employed in the State Governments for whole-time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority. The Authority may also make direct recruitment of any personnel or obtain the same from the Centre or other source as considered appropriate.

Sub-clause 7 : Administrative & Field Organisation Costs.

(1) : All expenses of the Authority (including the salary and expenses of the independent Members) shall be borne by the State Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan in equal shares. The expenses pertaining to a Member representing a State shall be borne by the State concerned. The cost of maintaining, operating and controlling the gauging and other hydrological stations in each State and the telecommunication systems for communicating the data shall be borne by the State concerned.

(2) The costs of construction of the storages power installations, diversion works, headworks and canal networks

shall be borne wholly by the State Government in whose territory the work is located except for works whose cost has been ordered by the Tribunal to be shared between two or more party States. Where the capital cost is thus shared, the operation and maintenance cost shall also be shared in the same proportion.

Sub-clause 8 : Powers, Functions & Duties of the Authority.

8(1) : The role of the Authority will mainly comprise co-ordination and direction. Normally all bilateral matters should be dealt with mutually by the States concerned and referred to the Authority only if there is a dispute.

8(2) : The Authority shall be charged with the power and shall be under a duty to do any or all things necessary, sufficient and expedient for the implementation of the Orders with respect to :

- (i) the storage, apportionment, regulation and control of the Narmada waters ;
- (ii) sharing of power benefits from Sardar Sarovar project;
- (iii) regulated releases by Madhya Pradesh;
- (iv) acquisition by the concerned State for Sardar Sarovar project of lands and properties likely to be submerged under Sardar Sarovar ;
- (v) compensation and rehabilitation and settlement of oustees ; and
- (vi) sharing of costs.

8(3) : In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the Authority shall perform inter alia the following functions :—

- (i) Madhya Pradesh or Gujarat, as the case may be, shall submit to the Authority the Sardar Sarovar Project Report, the Narmadasagar Project Report, the Omkareshwar Project Report and the Maheshwar Project Report. The Authority shall point out to the States concerned, the Central Water Commission, the Central Electricity Authority and Planning Commission any features of these projects which may conflict with the implementation of the Orders of the Tribunal. Any subsequent changes in the salient features or substantial increase in cost in respect of dams, power houses and canal headworks shall be reported to the Authority for taking appropriate action in the matter.
- (ii) The Authority shall decide the phasing and shall co-ordinate construction programmes of the Narmadasagar project and Sardar Sarovar Unit II—Canals with a view to obtaining expeditiously optimum benefits during and after the completion of the construction of the projects, having due regard to the availability of funds.
- (iii) The Authority shall obtain from the concerned States periodical progress reports both as to works and expenditure, and shall on receipt of such reports review the progress of construction of different units of the projects and whenever necessary advise the State concerned on the steps to be taken to expedite the work, except in respect of Unit I—Dam and Appurtenant Works and Unit III—Power Complex of Sardar Sarovar Project. The States shall submit, in respect of projects in Sub-clause 8(3)(i), completion reports to the Authority.
- (iv) The Authority shall issue appropriate directions whenever necessary for timely and full compliance by the concerned States with the Orders of the Tribunal in the matter of acquisition for and making available to Gujarat lands and properties likely to be submerged under the Sardar Sarovar Project and in the matter of compensation and rehabilitation of oustees thereunder.
- (v) The Authority shall cause to be established, maintained, and operated by the State Governments con-

cerned or any one or more of them, such stream and other gauging stations, equipped with automatic recorders where necessary, discharge, silt and evaporation observation stations and measuring devices as may be necessary from time to time for securing the records required for carrying out the provisions of the Orders. If deemed necessary, the Authority may require the installation, maintenance and operation by the State concerned of measuring devices of approved type at the head of main canals as also at the offtake of the canal for Rajasthan for measuring amount of water diverted from Narmada river system.

- (vi) Concurrent records shall be kept of the flow of the Narmada at all stations considered necessary by the Authority and the records correlated.
- (vii) The Authority shall frame rules of regulation and water accounting as per guidelines given in Clause IX. It shall determine the share of water of each State for every ten-day period for purposes of regulation and water accounting.
- (viii) The Authority shall ensure implementation of the Orders of the Tribunal in respect of (a) quantum and pattern of regulated releases by Madhya Pradesh; (b) payment for such regulated releases/sharing of costs.
- (ix) The Authority shall collect from the State concerned data of the areas irrigated by Narmada waters in each season, of power generated at each hydro-electric power station at and downstream of Narmadasagar, of withdrawals for domestic, municipal and industrial or any other purposes and of waters going down the river from Sardar Sarovar Project.
- (x) The Authority shall determine the volume of water flowing in the river Narmada and its tributaries in a water year (1st July to 30th June next year).
- (xi) The Authority shall determine from time to time the volume of water stored by each State in reservoirs and other storages and may for that purpose adopt any device or method.
- (xii) The Authority shall determine at appropriate periodic intervals the use of Narmada waters made by the States, or such of them as necessary, at any place or in any area at any time and for that purpose it may take note of all diversions or obstructions, whether natural or artificial or partly natural and partly artificial, from the river Narmada and its Tributaries and measure such use by any method as it deems fit.
- (xiii) The Authority or any of its duly authorised representative shall have power to enter upon any land and property upon which any project or development of any project, or any work of gauging evaporation or other hydrological station or measuring device has been or is being constructed, operated or maintained by any State for the use of Narmada water. Each State through its appropriate departments shall render all co-operation and assistance to the Authority and its authorised representatives in this behalf.
- (xiv) The Authority shall meet as often as necessary and decide on a proper management of waters including in particular the manner and details of withdrawals of waters from the storages on the Narmada river system in accordance with the Orders. In particular, the Authority shall meet at the end of filing season, and review the availability of waters in the storages on the Narmada river system and decide upon the pattern of their regulation for the next irrigation season, taking into account the carryover storages.
- (xv) The Authority shall give directions for a phased programme of construction for generation and transmission of power in fulfilment of the shares of power allocated to the three States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat from Sardar Sarovar and for payments therefor in accordance with the

Orders of the Tribunal. The Authority shall also ensure that generation and transmission of power from Sardar Sarovar complex are in accordance with the Orders.

- (xvi) The Authority shall issue appropriate directions for the establishment, maintenance and operation of an effective system of flood forecasting and flood control, including reporting of heavy precipitation, and telecommunication systems. The safety of a structure shall primarily be the responsibility of the Chief Engineer incharge of the structure and no decision or order shall be binding on him if in his opinion the safety of the structure will be endangered thereby. The Authority shall publish annually and make available to party States the data regarding operation of reservoirs during floods.

8(4) : In the light of its experience, the Authority may modify or add to the functions enumerated hereinabove in Sub-clauses 8(3)(i) to (xvi) by a resolution.

8(5) : All the concerned States shall submit to the Authority all the relevant information called for by the Authority in connection with the Narmada Valley Development expeditiously.

Sub-clause 9 : Annual Report of the Authority.

The Authority shall prepare and transmit to each of the four States as early as possible and in any case before the end of the current Water Year (1st July to 30th June) an Annual Report covering the activities of the Authority for the preceding year and to make available to each State on its request any information within its possession any time and always provide access to its record to the States and their representatives.

Sub-clause 10 : Records of the Authority and their Location.

The Authority shall keep a record of all meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have a suitable office where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the four States or their representatives at such times and under such regulations as the Authority may determine.

The location of the Central, Regional and Sub-regional offices of the Narmada Control Authority shall be determined by the Authority.

The headquarters of the Authority shall be at New Delhi till such time as it decides on its permanent location.

Sub-clause 11 : Contracts and Agreements.

The Authority shall enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties conferred or imposed on it.

Sub-clause 12 : Financial Provisions.

(1) All the capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority shall be borne by the four States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally. The Governments of the four States shall provide the necessary funds to the Authority to meet all capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority for the discharge of its functions.

(2) On the constitution of the Authority each of the Governments of the four States shall contribute Rs. 5,00,000 (Rupees five lakhs) to the fund of the Authority in the first instance.

(3) The Authority shall in the month of September of each year prepare detailed estimate of the amounts of money required during the twelve months from the first day of April of the ensuing year, showing the manner in which it is proposed to expend such money. The Authority shall on or before the fifteenth of October forward a copy of such detailed estimate to the concerned Chief Engineers of the four States and indicate the amount required to be contributed by each State for the ensuing financial year. Each of the State Governments



shall pay to the Authority its contribution as indicated by the Authority on or before the 30th day of April of the ensuing year.

(4) The Authority shall maintain detailed and accurate accounts of all receipts and disbursements and shall after the close of each financial year prepare an Annual Statement of Accounts and send copies thereof to the Accountants General as well as the concerned Chief Engineers of the four States. The form of the Annual Statement of Accounts shall be such as may be prescribed by rules. The Accounts maintained by the Authority shall be open for inspection at all reasonable times by the four States through their duly authorised representative or representatives.

(5) Disbursement shall be made from the fund of the Authority only in such manner as may be prescribed by the Authority. The Authority may incur such expenditure as it may think fit to meet any emergency in the discharge of its functions.

(6) The accounts maintained by the Authority shall be audited by the Comptroller & Auditor General of India or his nominee, who shall certify subject to such observations as he may wish to make on the annual accounts of the Authority. The Authority shall forward to the Accountants General and the concerned Chief Engineers of the four States copies of the Report of the Comptroller & Auditor General of India and shall include the same in its Annual Report.

Sub-clause 13 : Decision of the Authority.

The decisions of the Authority on all matters covered under Sub-clause 8 shall be final and binding on the four party States. However, there shall be a Review Committee which may suo motu or on the application of any party State review any decision of the Authority. In urgent cases the Chairman of the Review Committee may, on the application of the party State, grant stay of any order of the Authority pending final decision on review.

Sub-clause 14 : Review Committee.

14(1) : The Review Committee shall consist of five members including a Chairman as under :—

(i) Union Minister for Irrigation as the :	Chairman
(ii) Chief Minister of Madhya Pradesh :	Member
(iii) Chief Minister of Gujarat :	Member
(iv) Chief Minister of Maharashtra :	Member
(v) Chief Minister of Rajasthan :	Member

The Secretary of the Union Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Irrigation, shall be the Convenor of the Review Committee but shall not have any voting right.

In case there is President's rule in any of the States, the Governor of that State or his authorised representative will act as Member of the Review Committee.

14(2) : The Chief Ministers of the four States may nominate the respective Irrigation Ministers either generally or specially as the alternate Member with full powers of voting, taking decisions etc.

14(3) : The Review Committee may review the decision of the Authority at a meeting at which the Chairman and all the Members of the Review Committee are present. It is expected that the decisions of the Review Committee will be by consensus. Failing consensus it shall be by majority of votes of Members including the Chairman.

14(4) : Advance notice of the proposed meeting of the Review Committee, its agenda and agenda notes will be forwarded by the Convenor to the party States.

14(5) : The decision of the Review Committee shall be recorded in writing and shall be final and binding on all the States.

Sub-clause 15 : Construction Outside Jurisdiction Of The Authority.

The planning and construction of the projects will be carried out by each State through its own agencies, save and except to the extent prescribed in Sub-clause 16 of Clause XIV.

Sub-clause 16 : Supervisory Function Of The Authority Over Construction of Sardar Sarovar Project.

(1) The four party States have financial commitment in respect of Unit I—Dam and Appurtenant Works of the Sardar Sarovar Project and three of them, namely, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have such commitment in respect of Unit III—Power Complex of the Project. With a view to ensuring efficient, economical and early execution of these Units of the Project, and taking into account the financial commitments of the party States, it is desirable and necessary that a Construction Advisory Committee should be constituted for the purpose. We, therefore, order that such an Advisory Committee to be called Sardar Sarovar Construction Advisory Committee should be set up within three months from the date of publication of the Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

(2) The Construction Advisory Committee shall have a whole-time Secretary of the rank of Chief Engineer to be appointed by Union of India and such other staff as may be necessary.

(3) The Committee shall comprise.

- (i) The Secretary to the Government of India, in charge of Irrigation—Chairman.
- (ii) Chairman, Central Water Commission (CWC), or a Member of the CWC representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.
- (iii) Chairman, Central Electricity Authority (CEA), or a Member of the CEA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.
- (iv) Chairman, Narmada Control Authority (NCA) or an Independent Member of NCA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.
- (v) Joint Secretary (Financial Adviser) in the Union Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Irrigation).
- (vi) Secretaries in charge of Finance Department of Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan.
- (vii) Secretaries in charge of Irrigation Department of Governments of Gujarat and Rajasthan.
- (viii) Secretaries in charge of Power Department of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
- (ix) Secretaries in charge of Revenue Department or any other Department concerned with land acquisition of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
- (x) General Manager or Chief Engineers of Gujarat in charge of the project and Chief Engineers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan concerned with the Project.
- (xi) Chairman, State Electricity Boards of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
- (xii) Financial Adviser, Sardar Sarovar Project.

The Chairman may co-opt any other Member for any particular meeting.

(4) The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall :—

- (i) scrutinise the project estimates prepared for these works, advise necessary modifications and recommend the estimates for the administrative approval of the concerned Governments ;
- (ii) examine and make recommendation on all proposals pertaining to technical features and designs as may be referred to it by any of the party States and where necessary consult experts for the purpose.



- (iii) examine and make recommendation on the programme of construction of different parts of the project in a co-ordinated manner, keeping in view the funds available, the economics of the project and the desirability of obtaining quick results ;
- (iv) examine the requirement of funds for the construction of works and other purposes according to the approved programme and make necessary recommendations ;
- (v) examine and recommend, from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial, as it may deem necessary for the efficient execution of the project, to the General Manager/Chief Engineers, Superintending Engineers, Executive Engineers and Sub-Divisional Officers engaged in the execution of the project ;
- (vi) examine and, where necessary, recommend specifications for various classes of work;
- (vii) examine and make recommendation on all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the General Manager/Chief Engineers ;
- (viii) review progress reports, both for works and expenditure from the General Manager/Chief Engineers and recommend, where necessary, steps to be taken to expedite the work.
- (5) The headquarters of the Construction Advisory Committee will be fixed by the Committee.
- (6) The Construction Advisory Committee will frame rules regarding procedure and delegation of power for the purpose of carrying out its business.
- (7) The recommendations of the Construction Advisory Committee shall be conveyed to the Governments concerned by the Committee and copies sent to the Review Committee and Narmada Control Authority for information.
- (8) The recommendations of the Construction Advisory Committee shall normally be accepted by the State Governments concerned. In the event of any disagreement, the matter shall be referred to the Review Committee and the decision of the Review Committee shall be final and binding on all the concerned States
- In all matters relating to the construction of the Sardar Sarovar Dam and appurtenant works (Unit I), Power House and generating machinery (Unit III) and Transmission lines to feed power to Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat upto the next sub-station in each case, the Narmada Control Authority will carry out only such functions as do not specifically devolve upon the Construction Advisory Committee set up under Sub-Clause 16, Clause XIV.
- (9) The Construction Advisory Committee will be dissolved after three years of the completion of construction of Units I and III of the Sardar Sarovar Project. The post-construction management of Units I and III will be by Gujarat under the supervision of the Narmada Control Authority.
- (10) The expenditure of the Construction Advisory Committee will be borne by the four States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally.

## Sub-clause 17

Nothing contained in this Order shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between all the States concerned.

## Sub-clause 18 :

The Union of India has consented to participate in the Machinery to be established by the Order of the Tribunal, if so directed and to do its best to implement the decision of the Tribunal.

Accordingly, we direct the Union of India to participate in the Machinery set up by the Order of the Tribunal to implement the directions of the Tribunal specifically under Clauses 1(2), 4, 12(6), 13, 14 and generally to implement all the other directions so far as the Union of India is concerned.

## Clause XV : Order As To Costs Of Proceedings.

- (i) The States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan shall bear their own costs of appearing before the Tribunal. The expenses of the Tribunal shall be borne and paid by the aforesaid four State in equal shares. These directions relate to the references under Section 5(1) of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.
- (ii) The States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan shall bear their own costs of appearing before the Tribunal in the references under Section 5(3) of the said Act. The expenses of the Tribunal in respect of the aforesaid reference shall be borne and paid by the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan in equal shares.

## Clause XVI : Period Of Operation Of Certain Clauses Of The Final Order.

In addition to Clauses III and IV (mentioned in Clause V), our Orders in Clause VII with regard to Full Reservoir Level and Maximum Water Level of the Sardar Sarovar Dam, Clause VIII with regard to Sharing of Costs and Benefits, Clause IX with regard to Regulated Releases to be made by Madhya Pradesh for the Requirement of Sardar Sarovar Project, Clause X with regard to Payment to be made by Gujarat to Madhya Pradesh for such Regulated Releases, Clause XII with regard to Allocation of Costs of Sardar Sarovar Project between Irrigation and Power, Clause XIII with regard to Allocation of Irrigation Component of Cost of Sardar Sarovar Project between Gujarat and Rajasthan and Clause XIV as regards Machinery are all made subject to review at any time after a period of 45 years from the date of publication of the Decision of the Tribunal in the Official Gazette.

December 7, 1979.

Sd/-  
V. RAMASWAMI, Chairman

Sd/-  
A. K. SINHA, Member

Sd/-  
M. R. A. ANSARI, Member"

[F. 3/3/79-WD]  
C. C. PATEL, Secy.

